हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - CTHIN/25/A0716

मूक पत्रिका

निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...

वर्ष - 02 अंक - 186 बेमेतरा, गुरुवार 26 फरवरी 2026 रायपुर एवं बेमेतरा से प्रकाशित कुल पेज - 08 मूल्य - 5 रूपये डाक पंजीयन- दुर्ग/1743290201/2025-27

संक्षिप्त समाचार

पंजाब में मुफ्त योजनाओं की बौछार से गरमाई सियासत

चंडीगढ़। अगले साल होने वाले विधान सभा चुनावों से ठीक एक साल पहले पंजाब की सियासत इन दिनों एक नए मोड़ पर खड़ी है। चंडीगढ़ से लेकर दोआबा,माझा और मालवा में एक ही चर्चा है क्या राज्य में जनकल्याण की सबसे व्यापक तस्वीर उभर रही है? आम आदमी पार्टी की सरकार ने बीते समय में जिस तरह एक के बाद एक लोकहितकारी योजनाओं का ऐलान और जिस प्रकार उन्हें लागू किया है, उसने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार ने आम नागरिकों को सीधे राहत देने की नीति को अपनी पहचान बना लिया है। सबसे पहले 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली की सुविधा ने लाखों परिवारों का घरेलू बजट संतुलित किया। इसके साथ ही मुफ्त पानी और हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराकर सरकार ने बुनियादी जरूरतों को प्राथमिकता दी। सरकारी दावों के मुताबिक, इन योजनाओं का मकसद सिर्फ घोषणाएं करना नहीं, बल्कि आम आदमी के जीवन-स्तर को सीधे बेहतर बनाना है।

आठवीं की छात्रा की गला दबाकर हत्या, परीक्षा की राह में काल बनकर खड़ा था दरिंदा

बीकानेर। जिले के एक गांव में हुई 13 वर्षीय मासूम बालिका की नृशंस हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। तीन दिनों की कड़ी मशक्कत और सीसीटीवी खंगालने के बाद पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को डिटेन किया है, जिसने अपना जुर्म कुबूल कर लिया है। सीसीटीवी ने खोला राज) एसपी कावेंद्र सिंह सागर ने बताया कि पुलिस पिछले तीन दिनों से इलाके के सीसीटीवी फुटेज और संदिग्धों पर नजर रखे हुए थी। जांच में एक युवक संदिग्ध पाया गया, जो घटना वाले दिन (21 फरवरी) दोपहर करीब 12ः15 बजे घटनास्थल की ओर जाता और करीब 1 बजे वापस लौटता दिखाई दिया। दो दिनों की सघन पूछताछ के बाद आरोपी ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। जानकारी के अनुसार, मृतका 21 फरवरी को अपने घर से ढाणी के रास्ते आठवीं बोर्ड की परीक्षा देने स्कूल जा रही थी।

क्रिकेट मैदान बना खूनी जंग का अखाड़ा, युवक पर चाकू से हमला, दो आरोपी गिरफ्तार

गोपालगंज। बिहार के गोपालगंज में क्रिकेट खेलने को लेकर हुई चाकूबाजी में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे गोपालगंज से गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती की गई है। यह घटना कटेया थाना क्षेत्र के रामपुर ब्रह्मस्थान गांव की है। घायल युवक की पहचान रामपुर गांव के कमलेश कुशवाहा के रूप में हुई है। बताया जाता है कि रामपुर गांव में क्रिकेट खेलने के दौरान कुछ युवकों के बीच विवाद हो गया।

विधानसभा में अजय चंद्राकर ने उठाई आवाज

कंपनियां गिग वर्करों की जान जोखिम में डाले हुए हैं-अजय

रायपुर। संवाददाता

विधानसभा में आज पूर्व मंत्री एवं भाजपा विधायक अजय चंद्रकार ने गिग वर्करों के लिए कोई श्रम कानून नहीं होने पर सवाल उठाया। चंद्राकर ने आरोप लगाया की बड़ी कंपनियां दस मिनट में सामानों की डिलवरी का दावा कर छत्तीसगढ़ के बच्चों की जान को जोखिम में डाली हुई हैं। प्रश्नकाल में अजय चंद्राकर का सवाल था कि प्रदेश में स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकइट, रैपिडो (गिग वर्क) इस तरह की कितनी कंपनियां कार्यरत हैं? इन कंपनियों को कार्य करने हेतु अनुमति देने की प्रक्रिया क्या है? इन कंपनियों में कितने गिग वर्कर कार्यरत हैं? उनमें से छत्तीसगढ़ के कितने हैं? क्या इसके संबंध में कोई नियम-निर्देश हैं? गिग वर्करों की भर्ती हेतु शैक्षणिक या अन्य योग्यताएं निर्धारित की गई हैं? क्या इनके वेतन, श्रमावधि एवं सामाजिक सुरक्षा एवं आर्थिक सहायता हेतु नियम-शर्तें लागू होती हैं? इसकी निगरानी करने के लिये क्या व्यवस्था है एवं किस स्तर के अधिकारी द्वारा इनकी देख-रेख की जाती है? श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन की ओर से जवाब आया कि प्रदेश में श्रम विभाग अंतर्गत स्विगी, जोमेटो ब्लिंक इट, रेपिडो जैसे कंपनियाँ पंजीकृत नहीं हैं। उप मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) तथा कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय) व्दारा इस प्रकार की कंपनी पंजीकृत नहीं होने की जानकारी दी गई है। उक्त कंपनियों के श्रम विभाग अंतर्गत पंजीयन नहीं होने के कारण

इनमें कार्यरत गिग वर्कर की कुल संख्या तथा उनमें से छत्तीसगढ़ के गिग वर्करों की संख्या की जानकारी उपलब्ध नहीं है। श्रम विभाग व्दारा प्रवर्तित श्रम अधिनियम अंतर्गत उक्त कंपनियों को कार्य करने की अनुमति देने संबंधी कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं है। गिग वर्करों की भर्ती हेतु शैक्षणिक या अन्य योग्यताएं, वेतन एवं समयावधि निर्धारित करने का कोई प्रावधान नहीं है। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अंतर्गत भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा गिग एवं प्लेटफार्म वर्करों की सामाजिक सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा मण्डल का गठन केन्द्रीय सरकार व्दारा किये जाने का प्रावधान किया गया है। अजय चंद्राकर ने कहा कि पूर्व में प्लेसमेंट कंपनियों पर भी मैं इसी तरह प्रश्न लगाया था। गिग वर्करों का जमकर दोहन हो रहा है। ये कौन सी श्रेणी में आते हैं संगठित या असंगठित? मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि ये दोनों ही श्रेणी में नहीं आते। चंद्राकर ने पूछा कि इनकी सूरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्या कोई नियम या अधिनयम बनाएंगे। देवांगन ने कहा इनको लेकर जैसे ही भारत सरकार का कोई नियम बनेगा हम छत्तीसगढ़ में उसका पालन करेंगे। अजय चंद्राकर ने कहा कि जब तक कोई नियम नहीं बनेगा छत्तीसगढ़ के बच्चे क्या इसी तरह शोषण का शिकार होते रहेंगे?

बाधारहित जमीन की अनुपलब्धता के कारण तात्यापारा-शारदा चौक चौड़ीकरण रुका

विधानसभा में आज भाजपा विधायक सुनील सोनी के सवालों पर उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण एवं नगरीय प्रशासन) अरुण साव की ओर से जवाब आया कि तात्यापारा से शारदा चौक सड़क के चौड़ीकरण की कार्य योजना प्रारंभ होने में विलम्ब का मुख्य कारण बाधारहित जमीन की अनुपलब्धता है। सुनील सोनी का लिखित में सवाल था कि राजधानी रायपुर के तात्यापारा से शारदा चौक सड़क के चौड़ीकरण की कार्ययोजना प्रारंभ होने में विलंब के क्या कारण हैं? उक्त योजना के क्रियान्वयन में किन-किन विभागों को शामिल किया गया है? क्या कार्य प्रारंभ होने एवं पूर्ण होने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है? उप मुख्यमंत्री अरूण साव की तरफसे लिखित में जवाब आया कि राजधानी रायपुर के तात्यापारा से शारदा चौक सड़क के चौड़ीकरण की कार्य योजना प्रारंभ होने में विलंब का मुख्य कारण बाधारहित जमीन की अनुपलब्धता है।

राहुल गांधी ने कसा तंज

उदय भानु की गिरफ्तारी कायरता का प्रमाण है...

नई दिल्ली। भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए 'शर्टलेस प्रोटेस्ट' के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने इंडियन यूथ कांग्रेस (युवा कांग्रेस) के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस गिरफ्तारी का विरोध किया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि उदय भानु चिब की गिरफ्तारी तानाशाही प्रवृत्ति और कायरता का प्रमाण है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लिखा कि शांतिपूर्ण विरोध हमारी

ऐतिहासिक धरोहर है। यह हमारे खून में है और हर भारतीय का लोकतांत्रिक अधिकार है। मुझे युवा कांग्रेस के अपने बब्बर शेर साथियों पर गर्व है, जिन्होंने निडर होकर देश के हित में आवाज़ उठाई है। अमेरिका के साथ हुए ट्रेड डील में देश के हितों से समझौता किया गया है।

दिल्ली में ट्रिपल मर्डर से सनसनी

कसाई बने पति ने पत्नी और 3 मासूम बेटियों का रेता गला,वारदात के बाद आरोपी फरार

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली के आउटर नॉर्थ इलाके में एक ऐसा रूह कंपा देने वाला हत्याकांड सामने आया है जिसने पूरे शहर को झकझोर दिया है। चंदन पार्क में एक पिता ने अपनी ही तीन मासूम बेटियों और पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। दिल्ली के आउटर नॉर्थ जिले के चंदन पार्क इलाके में, जो समयपुर बादली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बुधवार सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात की खबर मिली। सर्वोदय विद्यालय के पास स्थित एक घर में एक ही परिवार के चार सदस्यों की लाशें मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतकों की पहचान अनीता (पत्नी) और उसकी तीन नाबालिग बेटियों के रूप में हुई है। पुलिस को जब इस घटना की सूचना मिली, तो टीम ने मौके पर पहुंचकर देखा कि एक ही कमरे में चारों शव खून से लथपथ पड़े थे। शुरुआती जांच में पता चला है कि सभी की हत्या धारदार हथियार से गला रेतकर की गई है। घर के

अंदर संघर्ष के निशान भी मिले हैं, जो यह दर्शाते हैं कि मरने से पहले पीड़ितों ने खुद को बचाने की कोशिश की होगी। दिल्ली पुलिस के अनुसार, इस सामूहिक हत्याकांड का मुख्य संदिग्ध घर का मुखिया और मृतका का पति मुंचन केवट है। मुंचन बुधवार सुबह से ही घर से लापता है और उसका फोन भी बंद आ रहा है। पड़ोसियों और रिश्तेदारों के लिए यह यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि मुंचन ऐसा कदम उठा सकता है। मृतकों की एक रिश्तेदार रुबी ने बताया कि जब उसने घर के अंदर देखा तो सबकी लाशें पड़ी थीं और उनके गले कटे हुए थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह परिवार दिखने में सामान्य और खुशहाल था। पुलिस अब उन कारणों की तलाश कर रही है जिसने एक व्यक्ति को अपनी ही बेटियों का कातिल बना दिया। जांच के दौरान आर्थिक तंगी, पारिवारिक कलह या मानसिक अस्थिरता जैसे पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। घटना की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। मौके पर क्राइम टीम और एफएसएल की टीमों को बुलाकर वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए गए हैं।

शेगांव में किया नेशनल आरोग्य मेले का उद्घाटन

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा अब औषधीय खेती से बढ़ेगी आय...

महाराष्ट्र/ एजेंसी

महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के शेगांव में बुधवार को चार दिवसीय नेशनल आरोग्य मेला 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस मेले का उद्घाटन करते हुए देश के नागरिकों के स्वास्थ्य और किसानों की आर्थिक उन्नति को लेकर एक नई राह दिखाई। उन्होंने अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया कि स्वस्थ नागरिक ही एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रपति का यह दौरा महाराष्ट्र के लिए स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में एक नई चेतना जागृत करने वाला माना जा रहा है।

राष्ट्रपति मुर्मू ने औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने की पुरजोर वकालत की। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन पौधों की खेती से न केवल किसानों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, बल्कि यह मिट्टी के स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने में मदद करेगा। राष्ट्रपति ने उपस्थित जनसमूह और कृषि विशेषज्ञों से आह्वान किया कि वे इस बात पर गंभीरता से विचार करें कि देश में औषधीय पौधों की खेती को व्यापक स्तर पर कैसे बढ़ाया जा सकता है। उनके अनुसार, पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक कृषि तकनीकों का संगम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदल सकता है। राष्ट्रपति ने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की सलाह देते हुए कहा कि दुनिया भर के लोग अब तनाव मुक्त और स्वस्थ जीवन के लिए योग को अपना रहे हैं। उन्होंने निवारक कदमों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नियमित व्यायाम, उचित आहार और संतुलित जीवनशैली अच्छे स्वास्थ्य की आधारशिला हैं।

राजकोट में 1489 अवैध मकानों पर गरजा बुलडोजर, सड़क पर आए 50 साल से रह रहे लोग

राजकोट। गुजरात के राजकोट में रविवार को प्रशासन का बुलडोजर जमकर गरजा। राजकोट नगर निगम ने शहर के जंगलेश्वर इलाके में अवैध कब्जों के खिलाफ एक बड़ा अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू कर दिया है। प्रशासन की इस भारी-भरकम कार्रवाई के तहत इलाके की 1,489 अवैध इमारतों को जमींदोज किया जाएगा। दशकों से बसी इन बस्तियों पर अचानक बुलडोजर चलने से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। इस बड़ी कार्रवाई की पृष्ठभूमि में राज्य के शीर्ष नेतृत्व का सख्त रुख है। अधिकारियों की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, राज्य के डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी से सीधे आदेश मिलने के बाद ही।

अनिल अंबानी का घर 'अबोड' हुआ जब्त

अब तक 15 हजार करोड़ रूपए की संपत्ति हो चुकी कुर्क-ईडी

नई दिल्ली/ एजेंसी

प्रवर्तन निदेशालय ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अनिल अंबानी के घर अबोड को जब्त कर लिया है, यह कुर्की हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई है। जब्त घर की कीमत 3,716 करोड़ बताई जा रही है, ईडी के मुताबिक अनिल और उनके समूह की कंपनीयों के खिलाफकब तक 15 हजार करोड़ से ज्यादा की कार्रवाई हो चुकी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उद्योगपति अनील अंबानी को बड़ा झटका देते हुए एकल न्यायाधीश पीठ के उस फैसले को खारिज कर दिया है, जिसमें उनके और रिलायंस

कम्युनिकेशंस के खिलाफ तीन बैंकों और एक ऑडिट फर्म को धोखाधड़ी की कार्रवाई से रोका गया था। डिवीजन बेंच के इस ताजा निर्णय के बाद अब बैंकों के लिए आगे की कार्रवाई का रास्ता साफहो गया है। मामले में शामिल प्रमुख बैंकों बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक को अब आरबीआई के वर्ष 2024 में जारी दिशा-निर्देशों के तहत अंबानी के खातों को 'फ्रॉड' घोषित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति मिल गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट की खंडपीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम ए अखंड शामिल थे, उन्होंने अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया था। अदालत ने 24 दिसंबर 2025 के एकल न्यायाधीश के अंतरिम आदेश को 'गैर-कानूनी' और प्रक्रियात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण करार देते हुए उसे निरस्त कर दिया।

एनसीईआरटी की 8वीं की किताब में 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार'

भड़के सीजेआई ने कहा-संस्था को बदनाम करने नहीं देंगे....

नई दिल्ली/ एजेंसी

एनसीईआरटी की कक्षा आठ की एक किताब में न्यायपालिका से जुड़ी विवादित सामग्री पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को गंभीर आपत्ति जताई थी। सूत्रों ने बुधवार को बताया कि एनसीईआरटी की कक्षा आठ की किताब में न्यायिक भ्रष्टाचार से संबंधित विवादास्पद अंशों को हटाया जा सकता है, क्योंकि सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। परिषद ने पुस्तक को अपनी वेबसाइट से हटा दिया है। इस बीच बताया जा रहा है कि एनसीईआरटी ने अध्याय से जुड़े विषय विशेषज्ञों और इसे मंजूरी देने वाले अधिकारियों की सिफारिशों की समीक्षा करने के लिए एक आंतरिक बैठक बुलाई है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक एनसीईआरटी के अध्यक्ष दिनेश प्रसाद सकलानी ने इस मुद्दे पर फोन और संदेशों का जवाब नहीं दिया। परिषद के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने यह कहते हुए टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है। सरकारी सूत्रों ने कहा कि एनसीईआरटी एक स्वायत्त संस्था है, लेकिन अध्याय जोड़ने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को सोच-समझकर निर्णय लेना चाहिए था। उन्होंने कहा कि यदि भ्रष्टाचार के मुद्दे को पाठ्यपुस्तक में शामिल करना ही था, तो इसे कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका ङ्क तीनों अंगों से संबंधित होना चाहिए था। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने बुधवार को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं

प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा प्रकाशित कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की नई पाठ्यपुस्तक में 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' के संदर्भों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि किसी को भी इस संस्था को 'बदनाम या अपमानित' करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह मामला मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने तब आया, जब वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने संशोधित पाठ्यपुस्तक की विषयवस्तु पर चिंता व्यक्त की। सिब्बल ने कहा कि कानूनी बिरादरी के सदस्य इस बात से बहुत चिंतित थे कि स्कूली बच्चों को न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ाया जा रहा था। उन्होंने इसे पूरी तरह से निंदनीय बताया। वरिष्ठ वकील ने शीर्ष अदालत को बताया, 'इस संस्था के सदस्य होने के नाते हमें यह जानकर गहरा दुख हुआ है कि कक्षा 8 के बच्चों को न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ाया जा रहा है। संस्था से हमारा गहरा संबंध है। हमारे पास पुस्तक की प्रतियां मौजूद हैं।' इस गंभीर मुद्दे को वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत के संज्ञान में लाया। वकीलों का तर्क था कि स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों को न्यायपालिका के प्रति इस तरह की नकारात्मक सामग्री पढ़ाया जाना बेहद चिंताजनक है, क्योंकि इससे उनके मन में न्याय प्रणाली के प्रति गलत संदेश जा सकता है।

सीजेआई सूर्यकांत की टिप्पणी-एक दिन रुकिए

इसके जवाब में, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि वह पहले से ही इस विवाद से अवगत थे और उन्हें न्यायपालिका के सदस्यों से इस मामले पर चिंता व्यक्त करने वाले कई पत्र प्राप्त हुए थे। मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पुस्तक की सामग्री से कई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी परेशान थे। जब सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह किया, तो सीजेआई ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर पहले ही कार्यवाही शुरू कर दी है। सीजेआई ने टिप्पणी की, 'एक दिन रुकिए। यह निश्चित रूप से पूरी संस्था के लिए चिंता का विषय है। मैं धरती पर किसी को भी इस संस्था की गरिमा को धूमिल करने और इसे बदनाम करने की अनुमति नहीं दूंगा। किसी भी कीमत पर मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। चाहे वह कितना भी ऊंचा पद पर हो, कानून अपना काम करेगा। मुझे पता है कि इससे कैसे निपटना है।'

विश्व महिला दिवस पर बेमेतरा में जल संरक्षण महाभियान : प्रत्येक घर में बनेगा रिचार्ज पिट

बेमेतरा/मूक पत्रिका

जिला बेमेतरा वर्तमान समय में गंभीर जल संकट की चुनौती का सामना कर रहा है। निरंतर गिरते भू-जल स्तर, अनियमित वर्षा, जल स्त्रोतों के सूखने तथा बढ़ती जल खपत के कारण आने वाले वर्षों में स्थिति और भी भयावह हो सकती है। जल के बिना जीवन की कल्पना असंभव है–ऐसे में जल संरक्षण एवं संवर्धन आज की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। इसी गंभीर परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए 08 मार्च 2026, विश्व महिला दिवस के पावन अवसर पर जिले में व्यापक स्तर पर ÷जल संरक्षण महाभियान÷ प्रारंभ किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक से अपने घर, आंगन या परिसर में रिचार्ज पिट (रिचार्ज पिट) का निर्माण करने का आह्वान किया गया है, ताकि वर्षा जल को संरक्षित कर भू-जल स्तर को बढ़ाया जा सके।

जल संकट : भविष्य की बड़ी चुनौती–विशेषज्ञों के अनुसार यदि अभी से जल संरक्षण के ठोस उपाय नहीं किए गए, तो आने वाले समय में पेयजल संकट गहराता जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को दूर-दूर से पानी लाने की समस्या और अधिक बढ़ सकती है। जल के अभाव का सीधा प्रभाव स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन और आजीविका पर पड़ता है। जल केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि जीवन की मूल आधारशिला है। यह कृषि उत्पादन, पर्यावरण संतुलन, जैव विविधता और मानव अस्तित्व का आधार है। इसलिए जल की प्रत्येक बूंद का संरक्षण हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।

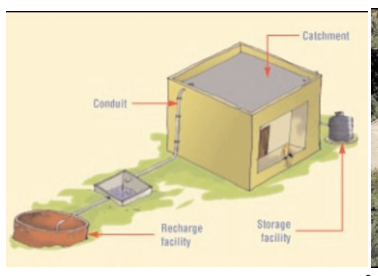

÷जल शक्ति से ही नारी सशक्त÷–विश्व महिला दिवस पर इस अभियान को विशेष रूप से महिलाओं को समर्पित किया गया है। जल संकट का सर्वाधिक प्रभाव महिलाओं पर ही पड़ता है–उन्हें घर और परिवार की जल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अतिरिक्त श्रम करना पड़ता है। ÷जल शक्ति से ही नारी सशक्त होती है÷ – क्योंकि जल के बिना वह अपने परिवार, बच्चों और समाज के भविष्य की कल्पना भी नहीं कर सकती। अतः इस दिवस पर जल संरक्षण का संकल्प लेना वास्तव में महिला सशक्तिकरण की दिशा में सार्थक कदम है।

रिचार्ज पिट : सरल, सस्ता और प्रभावी उपाय–जल संकट से निपटने का सबसे सरल एवं कारगर उपाय है रिचार्ज पिट का निर्माण 7 रिचार्ज पिट के लाभः वर्षा जल का भू-जल में पुनर्भरण, जल स्तर में वृद्धि, हैंडपंप एवं बोरवेल की आयु में वृद्धि, जलभराव की समस्या में कमी, भविष्य के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित 7 रिचार्ज पिट का निर्माण कम लागत में स्थानीय संसाधनों से किया जा सकता है। घर की छत से निकलने वाले वर्षा जल को पाइप के माध्यम से गड्ढे में डालकर, उसमें गिट्टी, रेत और पत्थर की परतें लगाकर जल को धरती में समाहित किया जाता है।

जन-जन तक पहुंचेगा जल संरक्षण का संदेश–÷जल संरक्षण महाभियान÷ के अंतर्गत ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों, स्वयं सहायता समूहों, महिला मंडलों, स्कूल-कॉलेजों एवं सामाजिक संगठनों के माध्यम से व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। रैली, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँ, दीवार लेखन एवं पोस्टर अभियान, सोशल मीडिया जागरूकता संदेश, स्कूलों में जल संरक्षण शपथ कार्यक्रम इन सभी माध्यमों से नागरिकों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा।

सामूहिक संकल्प से ही संभव होगा समाधान–जिले के समस्त सम्माननीय नागरिकों से अपील की गई है कि वे जल की एक-एक बूंद को व्यर्थ बहने से रोकें, घरों में रिचार्ज पिट का निर्माण करें, वर्षा जल संचयन को अपनाएँ, परिवार एवं समाज के प्रत्येक सदस्य को प्रेरित करें, बच्चों को जल संरक्षण के संस्कार दें 7 यदि प्रत्येक घर एक रिचार्ज पिट बनाए, तो पूरे जिले में हजारों जल संरचनाएँ निर्मित होंगी, जिससे भू-जल स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि संभव होगी।

जल बचाएँ – जीवन बचाएँ–विश्व महिला दिवस के अवसर पर यह केवल एक अभियान नहीं, बल्कि भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प है। आइए, हम सब मिलकर यह प्रण लें हम जल की एक-एक बूंद बचाएंगे, वर्षा जल का संरक्षण करेंगे, रिचार्ज पिट का निर्माण करेंगे, और बेमेतरा को जल संकट से मुक्त बनाएंगे।÷ 08 मार्च 2026 को अपने घर में रिचार्ज पिट बनाकर महिलाओं के सम्मान में जल संरक्षण का संकल्प लें। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी प्रकृति, मातृशक्ति और आने वाली पीढ़ियों के प्रति।

रायगढ़ में नशा मुक्ति अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई : 15 मेडिकल स्टोर्स को कड़ी चेतावनी, बिना पर्ची दवा बेची तो होगी जेल

रायगढ़/मूक पत्रिका

जिले में नशा मुक्ति अभियान के तहत जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए स्वापक एवं मनःप्रभावी औषधियों के अवैध क्रय-विक्रय और भंडारण पर रोक लगाने के उद्देश्य से व्यापक जांच अभियान चलाया।

यह कार्रवाई भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत की गई। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन तथा औषधि प्रशासन की संयुक्त टीम ने जिले के विभिन्न औषधि प्रतिष्ठानों में सघन जांच और निरीक्षण किया। इस दौरान कुल 15 मेडिकल स्टोर्स के संचालकों को नियमों का पालन सुनिश्चित करने हेतु कड़ी चेतावनी दी गई। अधिकारियों ने सख्त निर्देश दिए कि बिना डॉक्टर की वैध प्रिस्क्रिप्शन के किसी भी प्रकार की नशीली या मनः प्रभावी दवाइयों का क्रय-विक्रय न किया जाए। निरीक्षण के दौरान दवा विक्रेताओं को संबंधित कानूनों, भंडारण नियमों तथा रिकॉर्ड संधारण के संबंध में आवश्यक जानकारी भी प्रदान की गई।जिन मेडिकल स्टोर को इस संबंध में चेतावनी दी गई है इनमें गुजराल मेडिकल, सलूजा, लक्ष्मी, महामिया, प्रमोद, निरूपमा, आशीर्वाद, नेहा, विजय मेडिकल सहित अन्य मेडिकल स्टोर शामिल है। सहायक औषधि नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने कहा कि भविष्य में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी

कमरे में खून से लथपथ मिली युवक की लाश, पास में मिला कत्ता, घरघोड़ा थाना क्षेत्र में सनसनी

घरघोड़ा/मूक पत्रिका

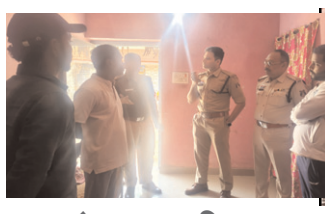

घरघोड़ा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां वार्ड नंबर 8 स्थित एक मकान के कमरे में 20 वर्षीय युवक की खून से लथपथ लाश मिलने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। मृतक की पहचान अभिषेक विश्वकर्मा पिता धनीराम विश्वकर्मा, उम्र 20 वर्ष, निवासी वार्ड 8 घरघोड़ा के रूप में की गई है।जानकारी के अनुसार घटना रात लगभग 10 बजे के आसपास की बताई जा रही है। परिजनों ने बताया कि अभिषेक खाना खाने के बाद अपने कमरे में चला गया था। कुछ देर बाद कमरे से किसी चीज़ के गिरने की आवाज आई। जब परिजन दरवाजे तक पहुंचे तो कमरा अंदर से बंद मिला। आवाज देने और फोन कॉल करने के बावजूद जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो परिजनों ने खिड़की से झांककर देखा। अंदर का दृश्य देख उनके होश उड़ गए – युवक खून से सना फर्श पर पड़ा था।घटना की सूचना तत्काल घरघोड़ा पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे को सील कर दिया है। घटनास्थल से एक धारदार हथियार (कत्ता) भी बरामद किया गया है। प्रारंभिक जांच में मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है।रात में ही उच्च अधिकारियों को घटना से अवगत करा दिया गया। पुलिस द्वारा फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया जा रहा है ताकि साक्ष्यों का बारीकी से परीक्षण किया जा सके। फिलहाल पुलिस विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच में जुटी है।इलाके में इस रहस्यमयी मौत को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं।

लापरवाही पर सख्त जिला पंचायत, ग्राम पंचायत सचिव निलंबित

प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा बैठक में अनुपस्थिति और राशि अनियमितता पर जिला सीईओ की बड़ी कार्रवाई

कार्यालय जिला पंचायत सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.)

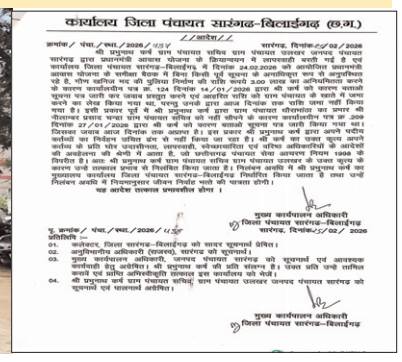

//आदेश//

सारंगढ़-बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

जिला पंचायत सारंगढ़-बिलाईगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी इंद्रजीत बर्मन (सीईओ) ने प्रशासनिक सख्ती का परिचय देते हुए ग्राम पंचायत सचिव पर बड़ी कार्रवाई की है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही, समीक्षा बैठक में बिना सूचना अनुपस्थित रहने तथा शासकीय राशि के संबंध में अनियमितता पाए जाने पर ग्राम पंचायत सचिव प्रभुनाथ कर्ष को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, 24 फरवरी 2026 को आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा बैठक में संबंधित सचिव बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहे। साथ ही गौण खनिज मद की पुलिया निर्माण राशि 3 लाख रुपये के आहरण के बाद समय पर ग्राम पंचायत खाते में जमा नहीं करने का मामला भी सामने आया। इस संबंध में पूर्व में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, किंतु निर्धारित अवधि में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। जिला सीईओ ने इसे कर्तव्य के प्रति उदासीनता, लापरवाही और छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के विपरीत आचरण मानते हुए निलंबन की कार्रवाई की है। निलंबन अवधि में संबंधित सचिव का मुख्यालय जिला पंचायत कार्यालय निर्धारित किया गया है तथा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।

जिला सीईओ की कार्यशैली की सराहना–जिले में विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिला सीईओ की सक्रिय और पारदर्शी कार्यशैली की व्यापक चर्चा हो रही है। प्रशासनिक अनुशासन बनाए रखने और योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए की गई यह कार्रवाई स्पष्ट संदेश देती है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने जिला प्रशासन की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा है कि ऐसी सख्त कार्रवाई से योजनाओं का लाभ वास्तविक हितग्राहियों तक समय पर पहुंचेगा और शासन की मंशा के अनुरूप विकास कार्यों में तेजी आएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील है।

छत्तीसगढ़ का बजट युवाओं और किसानों के लिए मील का पत्थर : शकुन्तला कश्यप

जगदलपुर/मूक पत्रिका

जिला पंचायत सदस्य शंकुतला कश्यप ने छत्तीसगढ़ के बजट 2026-27 की सराहना की है, इसे युवाओं, शिक्षा और कौशल विकास के लिए एक मील का पत्थर बताया है। उन्होंने कहा कि इस बजट से प्रदेश के युवाओं को आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे और छत्तीसगढ़ विकास की नई दिशा में आगे बढ़ेगा। बजट में शिक्षा और युवाओं के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि विश्वविद्यालयों और व्यावसायिक परीक्षा मंडल के लिए ?731 करोड़, स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना के लिए ?100 करोड़, तकनीकी शिक्षा को मजबूत करने के लिए ?50 करोड़, ष्ट्त्र॔ष्टश्व योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ?33 करोड़ और नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए ?35 करोड़। इसके अलावा, किसान कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, जिससे प्रदेश के किसानों को लाभ मिलेगा। शंकुतला कश्यप ने कहा कि इस बजट में शिक्षा, कौशल विकास, और नवाचार पर जोर दिया गया है, जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। साथ ही, किसानों के लिए भी कई कल्याणकारी योजनाएं शामिल की गई हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट छत्तीसगढ़ के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है।

हाईवे किनारे कैसे मिली निर्माण अनुज्ञा,पूर्व में एसडीएम ने ढहाया था अवैध निर्माण

केलो नदी के मुहाने पर बन गया ढाबा

रायगढ़/मूक पत्रिका

जो रोड चौड़ीकरण प्रस्तावित होती है, उसके किनारे कोई भी निर्माण की अनुमति नहीं मिलती। लेकिन रायगढ़ में पटवारी साथ हो तो कहीं भी कुछ भी बना सकते हैं। बिना एनओसी के आसानी से कमर्शियल निर्माण हो सकता है। केलो नदी और हाईवे के बीच में फिर से ढाबा का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण अनुज्ञा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। रायगढ़ से धरमजयगढ़ रोड पर आने वाले समय में और भी ज्यादा भारी वाहन चलेंगे। कोयला और स्टील परिवहन कभी कम नहीं होना है। यह हाईवे चौड़ा भी होना है। कई बार फोरलेन प्रोजेक्ट के रूप में इसे जोड़ा गया लेकिन निर्माण उस तरह का नहीं हो सका है। भविष्य में यह रोड चौड़ी होगी। लेकिन उसके पहले ही अवैध निर्माण शुरू हो गए हैं। पिछले साल एसडीएम रायगढ़ ने केलो डैम के फ्रंट में रोड किनारे सरकारी जमीन पर बने ढाबे को तोड़ा था। वहीं पर थोड़ी ही दूर पर एक और ढाबा बन रहा है। एनएच किनारे इस तरह के निर्माण की अनुमति कैसे मिली। इस रोड का चौड़ीकरण होना तय है। ऐसे में अनधिकृत निर्माण की वजह से सडक़ निर्माण की लागत बढ़ जाएगी। हाईवे किनारे ऐसे निर्माण की अनुमति पीडब्ल्यूडी आसानी से नहीं देता। डायवर्सन के पूर्व भी पटवारी से प्रतिवेदन लिया जाता है। पूछा जाता है कि सडक़ का चौड़ीकरण होने पर कितना असर पड़ेगा। पूरी तस्दीक के बाद ही निर्माण अनुज्ञा दी जाती है। लेकिन यहां किसने अनुमति दी, इस पर संदेह है। केलो नदी के किनारे ही कुछ जमीनें आदिवासी व्यक्तियों की हैं। कृषि भूमि पर निर्माण तो अवैध ही है। यह जमीन आने वाले समय में केलो नदी सौंदर्यीकरण के लिए भी ली जा सकती है। पूर्व में इसका एक प्रस्ताव तैयार किया गया था जिसे आगे नहीं बढ़ाया गया। पूर्व एसडीएम प्रवीण तिवारी ने सरकारी जमीन पर बने साहिल ढाबा को जमींदोज किया था।

केलो नदी किनारे होना था सौंदर्यीकरण–इस क्षेत्र में कई ऐसे निर्माण हैं, जिस पर कार्रवाई होनी है। एनएच और केलो नदी किनारे बिना अनुमति के हो रहे निर्माण पर केलो परियोजना विभाग भी आपत्ति नहीं करता है। केलो नदी के किनारे प्लांटेशन समेत कई काम होने थे, जिसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। यह काम हो जाता तो नदी के किनारे अतिक्रमण रुक जाता।

शहर में सक्रिय भूमाफिया उर्दना तिराहे पर अवैध प्लॉटिंग रोड बनाकर बेच दिए प्लॉट

कई क्षेत्रों में कमर्शियल जमीनें बिना अनुमति के बिक रही, RERA से पंजीयन ही नहीं

रायगढ़/मूक पत्रिका

एक बार फिर से रायगढ़ शहर में अवैध प्लॉटिंग का काम जोर पकड़ चुका है। रजिस्ट्री और नामांतरण में पटवारी का अभिमत अब बेमानी हो चुका है। कोई भी जमीन आसानी से टुकड़ों में बेची जा सकती है। आवासीय और व्यावसायिक प्लॉटिंग करने के पूर्व अनुमति की जरूरत ही नहीं है। उर्दना में तिराहे पर जमीन के बीच से रोड बनाकर प्लॉट बेचे जा चुके हैं। रायगढ़ हमेशा से अवैध प्लॉटिंग का गढ़ रहा है। कई भूमाफिया इस कारोबार को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। इनको किसी नियम की कोई परवाह नहीं होती है। उस पर से रजिस्ट्री करने के लिए प्रक्रिया आसान करने के कारण जमीनों को खरीदना-बेचना पहले की तुलना में सरल हो गया है।इसका फायदा आम लोगों को जितना हो रहा है, उससे कहीं अधिक भूमाफिया लाभ उठा रहे हैं। उर्दना में तिराहे के पास रोड किनारे ही एक बेशकीमती जमीन पर प्लॉटिंग की गई है। जमीन के बीच से सीसी रोड बनाई गई है। इसके आजू-बाजू में प्लॉट काटकर बेचे जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि रेरा से अनुमति लिए बिना ही जमीनें बेची गई हैं। शहर के कई लोगों ने हाईवे किनारे के प्लॉट खरीदे हैं। बिना किसी रुकावट के प्लॉटों की रजिस्ट्री करवा ली गई है। बेतरतीब विकास को रोकने के लिए आवासीय और कमर्शियल एरिया का डेवलपमेंट होना चाहिए। लेकिन रायगढ़ में भूमाफिया अपने हिसाब से प्लॉट काटकर बेच रहे हैं।

कई क्षेत्रों में बिक रही सरकारी जमीनें–एक ऐसा भी गिरोह शहर में सक्रिय है जो खाली पड़ी सरकारी जमीनों को बेच रहा है। सांगीतराई, बोंदाटिकरा, कौहाकुंडा, गढ़उमरिया, छातामुड़ा, अतरमुड़ा, विजयपुर आदि क्षेत्रों में सरकारी जमीनें बेची जा रही हैं। बाहर से आए लोगों को जमीन पर बसाने के बदले रुपए ऐंठे जा रहे हैं। इस वजह से इन इलाकों में अवैध बस्तियां बन गई हैं। कार्रवाई नहीं होने की वजह से नई स्लम बस्तियों का निर्माण हो रहा है।

डी ए वी जांता के बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण हेतु रैंक के आधार पर नासा(अमेरिका) व इसरो जाने का भी मिलेगा मौका

डीएवी जांता स्कूल से नासों खगोल अंतरिक्ष विज्ञान ओलंपियाड परीक्षा में 40 बालक-बालिकाओं ने हासिल किए गोल्ड मैडल

दाढ़ी/मूक पत्रिका

क्षेत्र के एक मात्र सी बी एस ई डी ए वी अग्रेजी माध्यम स्कूल में राष्ट्रीय खगोल अंतरिक्ष विज्ञान व अंतरिक्ष विज्ञान ओलंपियाड की परीक्षा में डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल जांता के कुल 40 चालीस छात्र- छात्राओं ने गोल्ड मेडल हासिल किया हैं। इन छात्रों को रैंक के आधार पर नासा (यू.एस.ए.अमेरिका), व इसरो की हवाई यात्रा भी उपलब्ध कराई जाएगी. राष्ट्रीय खगोल विज्ञान, विज्ञान ओलंपियाड परीक्षा के तहत द्वितीय चरण की परीक्षा 27 फ़रवरी को ऑनलाइन आयोजित होने जा रही है परीक्षा में अव्वल व रैंक आने पर इन बच्चों को रैंक के आधार पर शैक्षणिक भ्रमण हेतु विदेश जाने का व हवाई यात्रा करने का मौका भी मिलेगा। जिसमें कक्षा दूसरी से जयनीत निर्मलकर अगरी, तुलजा गिधवा, श्रेजल साहू ओड़िया, यश चंद्राकर बीसनपुरा, कक्षा तीसरी से श्रेया पाठक पचभैया,भूपेन्द्र कुमार साहू खुरुशबोर्ड,प्राची साहू छीरहा,रूद्र चंद्राकर ओड़िया, कक्षा चौथी हेमांशु चंद्राकर दमाईडीह, मयंक निर्मलकर अगरी, सागर बिरसिंधी,कक्षा पांचवीं से आदित्या दुबे, दाढ़ी, भावेश कुमार चंद्राकर दाढ़ी, ज्योति कश्यप मोहतरा, योगिता साहू उमरिया, भावेश कुमार गहिरे बिरनपुर, मेदिशंकर चंद्राकर करही तेंदो,

कक्षा छठवीं से रोहाणी चंद्राकर बीसनपुरा,प्रवीण कुमार साहू प्रतापपुर,योगिता दिवाकर धोराबन्द,नीलय जायसवाल खण्डसरा,निशांत साहू उमरिया,तुषार साहू कारेसरा, मयंक चंद्राकर अमचो,साक्षी सिन्हा सैगोना, पियुष पेटल मोहतरा,

कक्षा सातवी से राम ध्रुव पुलिस कॉलोनी बेमेतरा, ओमकार चंद्राकर कोयलारी,उदयप्रकाश वर्मा कन्हेरा, अभिज्ञान सिंह छिरहा,मान्या मिश्रा जांता,अभिषेक जायसवाल पच्भैया,निखिल निर्मलकर कर्चुवा, कक्षा नवमी से आदित्य पटेल कठौतिया,भूमिका वर्मा कोदवा,आयुष कुमार साहू, खुरुशबोर्ड,टिकेश्वर चंद्राकर खण्डसरा दशरंगपुर, कक्षा दसवीं से मोक्ष साहू घिवरी बेमेतरा,डोलीचंद्रकार कृतबाँधा- का गोल्ड मैडल के साथ द्वितीय लेवल के चयननित हुए हैं। डी ए वी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल के प्रथम चरण में कुल (105)एक सौ पांच विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय नासों ओलंपियाड परीक्षा में शामिल हुए थे जिसमें कक्षा दो से कक्षा दसवी तक के छात्र-छात्राओं का राज्य स्तरीय व राष्ट्रीय स्तरीय पर विद्यालय के कुल 53 विद्यार्थियों ने रैंक हासिल किए हैं, इनमें से 40 चालीस विद्यार्थियों ने द्वितीय चरण के लिए गोल्ड मैडल के साथ में चयनित हुआ हैं। संस्था के प्राचार्य पी एल जायसवाल ने कहा है कि ऐसे परीक्षा का आयोजन व इस तरह से प्रतियोगिता परीक्षा,व विभिन्न राष्ट्रीय लेवल के प्रतियोगि परीक्षा दिलाने से विशेष कर अंतरिक्ष विज्ञान व नवाचार के क्षेत्रों में छिपी वैज्ञानिक प्रतिभा को निखारने का अवसर मिलता हैं, वास्तव में हमारे स्कूल के लिए यह बड़ी गर्व की बात है इससे पहले भी डी ए वी जांता के छात्र छात्राओं ने राज्य स्तर व राष्ट्रीय स्तर में अनेक पुरुस्कार प्राप्त किए हैं,अब तक 119 छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर पर अवॉर्ड प्राप्त कर चुके हैं।संस्था के प्राचार्य के सुपुत्र पियुष जायसवाल व साक्षी जायसवाल अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैंड्ढ इनका प्रारंभिक शिक्षा डी ए वी स्कूल में हुए है व खगोलशास्त्र में रिसर्च किए है, साथ ही नवाचार में अविष्कार करते हुए सबसे कम उम्र के बाल वैज्ञानिक बने हैं दोनों को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से नवाजा गया है। प्राचार्य जायसवाल ने विद्यार्थियों को हमेशा इसी तरह आगे बढ़ने हेतु प्रेरित करते रहते हैं जिसका सीधा फायदा विद्यालय के विद्यार्थियों को हो रहा हैं। डी ए वी प्रबंधन से छत्तीसगढ़ डी ए वी संस्थान प्रमुख व रीजनल ऑफिसर प्रशांत कुमार व डी ए वी सी जी जोन- डी के असिस्टेंट रीजनल ऑफिसर डॉ बी पी साहु, विद्यालय प्राचार्य पी एल जायसवाल, व शिक्षकगण सहित अभिभावकों ने सभी विद्यार्थियों को इस बड़ी उपलब्धि के लिए बधाई व शुभकामनाएं दिए है।

उदयभानु चिब की गिरफ्तारी के विरोध में युवा कांग्रेस का प्रदर्शन, प्रधानमंत्री का पुतला दहन

कांकेर/मूक पत्रिका

भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिब की गिरफ्तारी के विरोध में युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेंद्र दुबे के मार्गदर्शन में कांकेर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी का पुतला दहन कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया।युवा कांग्रेस शहर अध्यक्ष जीशान अली के नेतृत्व में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेसजन एवं युवा कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए गिरफ्तारी को अलोकतांत्रिक एवं दमनात्मक कार्रवाई बताया, प्रदर्शनकारियों ने कहा कि युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जबरन गिरफ्तारी लोकतंत्र की आवाज को दबाने का प्रयास है, जिसे कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया। युवा कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि इस मामले में जल्द उचित कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रही।इस अवसर पर कांकेर शहर अध्यक्ष यासीन कराणी, कांकेर मंडल अध्यक्ष मुकेश तिवारी, दीपक सोरी, पार्षद मतीन खान, पार्षद, चंद्रलोक सिंह ठाकुर, पार्षद बबलू देवांगन, जिला पंचायत सदस्य मिर्दुला भास्कर, पूर्व पार्षद विजय यादव, पूर्व पार्षद, सतीश दीपक, उदय प्रकाश शर्मा, अजय भासवानी, लतीफ मेमन, जिला युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष सत्यार्थ करायत, जिला महासचिव विनय सिंह ठाकुर, बांटी सोनकर, सोमेश सोनी, प्रतीक मेश्राम, यशपाल कांगे, अभय राय, फैजल खान, निर्भय राव, झमित कांगे, धनु साहु, चंद्रदीप केमरो, फलेंद्र साहु, अंकित राजपूत, अखिलेश टंडन, नितेश नरेटी वाशु रजक, ऋतिक सारथी, कमलेश साहु अन्य सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

विद्युत उपभोक्ताओं के अधिकारों पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

ग्राम बहेरा में एक दिवसीय शिविर में ग्रामीणों को दी गई महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी

बेमेतरा/मूक पत्रिका

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा के निर्देशानुसार ग्राम बहेरा में विद्युत उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने हेतु एक दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को विद्युत उपभोक्ता होने के नाते प्राप्त अधिकारों एवं शिकायत निवारण की प्रक्रिया की जानकारी देना था। शिविर में सहायक प्रतिरक्षा अधिवक्ता आयुष शुक्ला ने उपस्थित ग्रामवासियों को बताया कि प्रत्येक उपभोक्ता को निर्धारित वोल्टेज एवं गुणवत्ता के साथ नियमित विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है। अनावश्यक एवं बार-बार विद्युत कटौती नहीं की जा सकती। निर्धारित समय से अधिक कटौती होने पर उपभोक्ता मुआवजे की मांग कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि विद्युत बिल स्पष्ट, समझने योग्य तथा वास्तविक मीटर रीडिंग पर आधारित होना चाहिए। लंबे समय तक औसत बिलिंग नहीं की जा सकती। यदि उपभोक्ता को बिल पर संदेह हो तो उन्हें मीटर जांच कराने का अधिकार है। मीटर में समस्या की शिकायत करने पर 15 दिनों के भीतर उसका निराकरण किया जाना अनिवार्य है। यदि निर्धारित समय में समाधान नहीं होता, तो उपभोक्ता उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सहायक प्रतिरक्षा अधिवक्ता देवेंद्र साहू ने बताया कि विद्युत संबंधी शिकायतें तीन स्तरों पर की जा सकती हैं जिसमे ग्रिवेंस रिड्रेसल ऑफिसर (ष्टत्नक्र), विद्युत लोकपाल (Electricity Ombudsman), आवश्यकता होने पर उपभोक्ता आयोग शामिल हैं 7 अमन दुबे ने जानकारी दी कि कोई भी पात्र व्यक्ति निर्धारित शुल्क जमा कर नया बिजली कनेक्शन प्राप्त करने का अधिकारी है तथा वितरण कंपनी मनमाने ढंग से आवेदन अस्वीकार नहीं कर सकती। प्रतिरक्षा अधिवक्ता पी. राजेश्वरी ने मीटर जांच एवं परीक्षण के अधिकार के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि उपभोक्ता लिखित आवेदन देकर मीटर टेस्टिंग की मांग कर सकता है। यदि मीटर खराब पाया जाता है तो बिल में आवश्यक संशोधन किया जाएगा। शिविर के दौरान ग्रामीणों को निःशुल्क विधिक सहायता के महत्व एवं आपराधिक मामलों में लीगल एड डिफेंस काउंसिल की भूमिका के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया।

भाजपा युवा मोर्चा का विस्तार, कुसमी में उमेश बुनकर बने मंडल अध्यक्ष, विवेक कश्यप व अभय गुप्ता को महामंत्री की जिम्मेदारी

किरण सिंह देव के मार्गदर्शन में उमेश बुनकर को मंडल अध्यक्ष तथा विवेक कश्यप व अभय गुप्ता को मंडल महामंत्री का दायित्व

उमेश बुनकर
युवा मोर्चा कुसमी मंडल अध्यक्ष

अभय गुप्ता
मंडल महामंत्री युवा मोर्चा मंडल कुसमी

विवेक कश्यप
मंडल महामंत्री युवा मोर्चा मंडल कुसमी

कुसमी/मूक पत्रिका

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष किरण सिंह देव एवं प्रदेश संगठन महामंत्री साय जी के मार्गदर्शन में तथा युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष राहुल टिकरिया के निर्देशानुसार और भाजपा जिला अध्यक्ष ओमप्रकाश जयसवाल की अनुशंसा पर भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला पदाधिकारी एवं कार्यसमिति सदस्यों की घोषणा की गई है। घोषणा के तहत कुसमी ब्लॉक से उमेश बुनकर को मंडल अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है। वहीं मंडल कुसमी से विवेक कश्यप और अभय गुप्ता को महामंत्री की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है।संगठन ने उनके लंबे राजनीतिक अनुभव, सक्रिय भूमिका और संगठन के प्रति समर्पण को देखते हुए यह अहम दायित्व सौंपा है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि ये सभी पदाधिकारी अपने नेतृत्व कौशल और कार्यक्षमता से संगठन को नई ऊर्जा प्रदान करेंगे।वरिष्ठ नेताओं ने विश्वास जताया है कि मंडल अध्यक्ष उमेश बुनकर के साथ मंडल महामंत्री विवेक कश्यप और अभय गुप्ता युवा मोर्चा को और अधिक मजबूत करेंगे तथा पार्टी की नीतियों को गांव-गांव तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएंगे। इन नियुक्तियों से कुसमी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है और समर्थकों ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी है।

मकान खरीदने वालों के लिए सुनहरा अवसर, सारंगढ़ में आज शाम तक हाऊसिंग बोर्ड का शिविर

सारंगढ़ बिलाईगढ़/ मूक पत्रिका

सारंगढ़ में आज बुधवार की शाम तक मकान खरीदने वालों के लिए सुनहरा अवसर आया है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की ओर से तुर्की तालाब के पास जवाहिर भवन के प्लाट में हाऊसिंग बोर्ड का शिविर आयोजन किया गया है। इच्छुक नागरिकों को आवास के मूल्य, भवन का आकार, किश्त, छूट आदि की जानकारी दी जाएगी। हाउसिंग बोर्ड के भवन पंजीयन हेतु लोगों की सुविधा हेतु हाउसिंग बोर्ड ऑफिस रायगढ़ के टीम मौजूद हैं।

इलेक्ट्रिशियन, एसी टेक्निशियन, डीटीपी कंप्यूटर कोर्स के लिए 26 फ़रवरी को होगा काउंसलिंग

सारंगढ़ बिलाईगढ़। जिला कौशल विकास प्राधिकरण सारंगढ़ बिलाईगढ़ के द्वारा 18 वर्ष या अधिक उम्र के युवा को निशुल्क ट्रेनिंग दिया जायेगा, जिसके लिए 26 फरवरी को काउंसलिंग की जाएगी। इलेक्ट्रिकल डोमेस्टिक सॉल्यूशंस (सहायक इलेक्ट्रिशियन) कोर्स के लिए दसवीं उत्तीर्ण युवा शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सारंगढ़ में और डीटीपी कंप्यूटर कोर्स के लिए 12 उत्तीर्ण युवा केपी युवा कौशल प्रशिक्षण केंद्र बंधापाली (बरमकेला रोड)में शामिल हो सकते हैं। इसी प्रकार 8वी उत्तीर्ण युवा, इलेक्ट्रिकल डोमेस्टिक सॉल्यूशंस और एसी फील्ड टेक्निशियन के निशुल्क कोर्स के लिए आईटीआई सरिया में आयोजित काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं।

झूठी शिकायतों की परतें खुलीं: जांच में सरपंच पर लगे आरोपों की नहीं हुई पुष्टि

ग्राम पंचायत रीवापार में 15वें वित्त योजना के कार्य नियमपूर्वक, ग्रामीणों ने सरपंच के समर्थन में दिया बयान

सारंगढ़/मूक पत्रिका

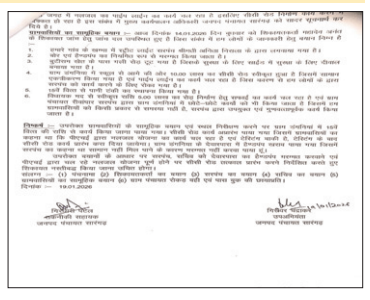

सारंगढ़ जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत रीवापार में 15वें वित्त आयोग की राशि में गड़बड़ी और फर्जी बिल के माध्यम से आहरण के लगाए गए आरोपों पर प्रशासनिक जांच के बाद तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। जांच प्रतिवेदन में सरपंच पर लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है और कार्यों को प्रक्रिया अनुसार संपादित किया जाना पाया गया है।शिकायत के आधार पर जनपद पंचायत स्तर से जांच टीम गठित की गई थी, जिसमें संबंधित अधिकारियों ने स्थल निरीक्षण कर दस्तावेजों का परीक्षण किया। जांच के दौरान पंचायत सचिव, सरपंच एवं ग्रामीणों के बयान भी दर्ज किए गए। दस्तावेजों की समीक्षा में यह पाया गया कि 15वें वित्त आयोग अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की राशि का उपयोग प्रस्ताव एवं नियमों के अनुरूप किया गया है। सरपंच श्रीमती अनीता निराला ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर ही कार्यों की स्वीकृति एवं भुगतान की प्रक्रिया अपनाई गई। पीएफएमएस के माध्यम से हितग्राहियों एवं सप्लायरों के खातों में भुगतान किया गया, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हुई। उन्होंने कहा कि सीसी रोड, स्ट्रीट लाइट एवं अन्य विकास कार्य गांव की आवश्यकता के अनुरूप कराए गए हैं।ग्राम पंचायत सचिव ने भी पुष्टि की कि सभी भुगतान शासन के निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन माध्यम से किए गए तथा आवश्यक अभिलेख सुरक्षित रखे गए हैं। जांच के दौरान मौके पर कई कार्य पूर्ण अथवा प्रगति पर पाए गए। ग्रामीणों ने भी सरपंच के पक्ष में बयान देते हुए कहा कि गांव में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की गई है, हैंडपंपों का नियमित रखरखाव हो रहा है तथा सीसी रोड निर्माण कार्य से आवागमन सुगम हुआ है। कुछ निर्माण कार्य सामग्री उपलब्धता के कारण प्रगति पर हैं, जिन्हें शीघ्र पूर्ण किया जाएगा।ग्रामवासियों का कहना है कि विकास कार्यों को लेकर अनावश्यक विवाद खड़ा करना उचित नहीं है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि निराधार शिकायतों पर अंकुश लगाया जाए ताकि पंचायत का विकास कार्य बाधित न हो। कुल मिलाकर जांच रिपोर्ट के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि पंचायत में विकास कार्य नियमानुसार किए गए हैं और सरपंच के विरुद्ध लगाए गए आरोप प्रमाणित नहीं हो सके। ग्रामीणों ने एकजुट होकर विकास की गति बनाए रखने का संकल्प दोहराया है।

नारियल की खेती से नई राह : कलेक्टर संजय कन्नौजे ने शिव प्रसाद प्रधान के फार्म का किया निरीक्षण..

सारंगढ़ बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

सरिया तहसील अंतर्गत बुदबुदा ग्राम पंचायत के नवापारा (छोटे) गांव में पारंपरिक खेती के साथ आधुनिक प्रयोग अब जिले के लिए मिसाल बनता जा रहा है। रिटायरमेंट के बाद खेती को नया रूप देने वाले शिव प्रसाद प्रधान के नारियल फार्म का आज बुधवार को कलेक्टर संजय कन्नौजे ने दौरा कर निरीक्षण किया।कलेक्टर ने खेत में लगे नारियल की खेती और उसके साथ की जा रही क्रॉस फॉर्मिंग को नजदीक से देखा और इसे किसानों के लिए लाभकारी मॉडल बताया।

रिटायरमेंट के बाद खेती में नया प्रयोग-दिसंबर 2023 में असिस्टेंट वेटनरी फील्ड ऑफिसर पद से रिटायर हुए शिव प्रसाद प्रधान ने खेती को ही अपनी नई पहचान बनाया। उन्होंने 3 एकड़ जमीन में नारियल की खेती शुरू की, जो इस क्षेत्र में कम देखने को मिलती है। इस पूरे प्रयास में उनके बेटे सानंद प्रधान भी पूरी सक्रियता के साथ जुड़े हुए हैं। पिता-पुत्र मिलकर खेत को आधुनिक फार्म के रूप में विकसित कर रहे हैं।

नारियल के साथ क्रॉस फॉर्मिंग से आमदनी-नारियल के पौधों के बीच खाली जगह को उपयोग में लाते हुए गेंदा, धनिया और अरबी की खेती की जा रही है। कृषि और उद्यानिकी विभाग के मार्गदर्शन में शुरू की गई इस क्रॉस फॉर्मिंग से अब आमदनी भी शुरू हो चुकी है। गेंदा फूल की बिक्री से त्वरित आय मिल रही है, वहीं नारियल भविष्य में स्थायी आमदनी का मजबूत जरिया बनने की उम्मीद जगा रहा है।

कलेक्टर ने की सराहना-निरीक्षण के दौरान कलेक्टर संजय कन्नौजे ने किसान शिव प्रसाद और सानंद से चर्चा की और कहा कि यदि वैज्ञानिक पद्धति से खेती की जाए तो पारंपरिक फसलों के साथ नई फसलों से बेहतर लाभ लिया जा सकता है।उन्होंने कृषि और उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस तरह के सफल प्रयोगों को अन्य किसानों तक पहुंचाया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान आधुनिक खेती की ओर कदम बढ़ाएं।

युवाओं के लिए प्रेरणा बना फार्म-शिव प्रसाद प्रधान का फार्म अब सिर्फ खेती तक सीमित नहीं रह गया है। गांव और आसपास के इलाकों से युवा यहां पहुंचकर नारियल और क्रॉस फॉर्मिंग की जानकारी ले रहे हैं। शिव प्रसाद का कहना है कि सही देखभाल और तकनीक के साथ खेती की जाए तो गांव में रहते हुए भी अच्छी और स्थायी आमदनी संभव है। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर संजय कन्नौजे के साथ जिला पंचायत सीईओ इंद्रजीत बर्मन, एसडीएम वर्षा बंसल, डिप्टी कलेक्टर, अजय पटेल सीईओ जनपद पंचायत बरमकेला, सरिया तहसीलदार कोमल साहू सहित अन्य विभागीय अधिकारी कर्मचारी और स्थानीय पंचायत के प्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं पंचायत बनने के बाद बुदबुदा पंचायत में किसी कलेक्टर के पहली बार दौरा कार्यक्रम होने की वजह से ग्रामीणों में उत्साह का माहौल रहा और अपने कलेक्टर से मिलने बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

रेत के अवैध परिवहन पर राजस्व और पुलिस टीम की लगातार कार्रवाई जारी, 2 दिन में 12 ट्रैक्टर जब्त..

सारंगढ़ बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ संजय कन्नौजे के निर्देश पर रेत के अवैध परिवहन में संलिप्त वाहनों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार और बुधवार को कुल 12 ट्रैक्टर पर सरिया तहसीलदार कोमल साहू और थाना की टीम ने कार्यवाही करते हुए रेत से भरे वाहनों को सरिया थाना के सुरक्षार्थ में रखा है। यह कार्रवाई राजस्व और सरिया पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा किया गया है। बता दें कि राज्य के मुख्य सचिव ने सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में रेत के अवैध परिवहन को लेकर मीटिंग में नाराजगी जाहिर करते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद कलेक्टर संजय कन्नौजे ने जिले के सभी तहसील में राजस्व और पुलिस टीम में टास्क फोर्स का गठन कर कार्रवाई करने कहा गया था। उसी के परिपालन में मंगलवार और बुधवार को सरिया तहसीलदार कोमल साहू और थाना सरिया की टीम द्वारा सरिया क्षेत्र में रेत के अवैध परिवहन में संलिप्त 12 ट्रैक्टर पर कार्यवाही करते हुए थाना सरिया के सुरक्षार्थ में दिया गया। इनमें ट्रेक्टर के वाहन क्रमांक ष्ठत्न13रु2643, ष्ठत्न13श्व7957, 1 नया सोनालिका ट्रेक्टर आदि शामिल है। यह कार्यवाही छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 और खान एवं खनिज विकास अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत की गई। कलेक्टर संजय कन्नौजे ने कहा कि इस तरह खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर संलिप्त सभी वाहनों पर लगातार कार्यवाही जारी रहेगा। वहीं ओवर स्पीड, नाबालिगों द्वारा वाहन चलने और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

आवास, मनरेगा, बिहान एवं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कार्यों में तेजी लाने पर जोर

कलेक्टर ने पंचायत विभाग कि विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक लेकर दिए सख्त निर्देश

बेमेतरा/मूक पत्रिका

जिला पंचायत सभागार में कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई ने ग्रामीण विकास से जुड़ी प्रमुख योजनाओं–मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), बिहान योजना तथा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत संचालित निर्माण कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक ली। बैठक में जिला पंचायत सीईओ प्रेमलता पदमाकर, उप संचालक जिला पंचायत सुश्री देसाई, विभिन्न जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी, जिला समन्वयक एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान कलेक्टर ने योजनावार प्रगति की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन हितग्राहियों के आवास निर्माण कार्यों में प्रगति अपेक्षाकृत कम है, उन्हें गंभीरता से लेते हुए एक माह के भीतर कार्य पूर्ण कराने की कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को समय पर पक्के आवास उपलब्ध कराना है, इसलिए लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए उन्होंने समय-सीमा निर्धारित कर लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। मनरेगा की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि जिले में श्रमिकों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने ब्लॉक स्तरीय मनरेगा कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देशित किया कि अधिक से अधिक श्रमिकों का पंजीयन एवं रोजगार उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दें। कार्यस्थलों पर श्रमिकों की संख्या बढ़ाई जाए तथा भुगतान प्रक्रिया समयबद्ध हो। उन्होंने कहा कि मनरेगा केवल रोजगार उपलब्ध कराने की योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण आधारभूत संरचना सुदृढ़ करने का माध्यम भी है, इसलिए गुणवत्ता एवं पारदर्शिता दोनों सुनिश्चित की जाएं। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत निर्माणाधीन फीकल स्लज मैनेजमेंट यूनिट के प्रारंभ न होने पर कलेक्टर ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने जिला समन्वयक एवं संबंधित सीईओ को निर्देशित किया कि प्लांट को शीघ्र संचालन में लाया जाए। आसपास के गांवों से स्लज मंगाकर प्लांट को रनिंग स्थिति में लाने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए। कलेक्टर ने यह भी कहा कि निजी व्यक्ति या संस्थाएं यदि गटर एवं सेप्टिक टैंक की सफाई कर गांवों में इधर-उधर खुले स्थानों पर मल त्याग सामग्री फेंकते पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि ऐसे सभी वाहनों को शासन द्वारा स्थापित प्लांट में ही स्लज निस्तारण करने के लिए बाध्य किया जाए, ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित हो सके। बिहान योजना की समीक्षा के दौरान महिला स्व-सहायता समूहों की गतिविधियों को और सशक्त करने, आजीविका गतिविधियों में वृद्धि करने तथा बैंक लिंकेज की स्थिति में सुधार लाने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि समूहों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस पहल की जाए और उनके उत्पादों के विपणन की व्यवस्था मजबूत की जाए।

बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में की गई घोषणाओं के लंबित कार्यों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण कराया जाए तथा प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व सभी स्वीकृत कार्यों का क्रियान्वयन पूर्ण कर लिया जाए और संबंधित पोर्टल में प्रविष्टियां समय पर की जाएं, ताकि किसी प्रकार की वित्तीय या प्रशासनिक बाधा उत्पन्न न हो। कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई ने बैठक के अंत में कहा कि सभी अधिकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में गंभीरता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य करें। ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाएं सीधे आमजन के जीवन स्तर को प्रभावित करती हैं, अतः लक्ष्य प्राप्ति के साथ-साथ गुणवत्ता भी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने समय-समय पर फील्ड निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति की समीक्षा करने के भी निर्देश दिए।

संपादकीय

लोगों के अधिकारों पर भारी पड़ रहे सोशल मीडिया

आज एक मोबाइल नंबर लेने से लेकर बैंक में खाता खुलवाने तक, हर जगह संबंधित व्यक्ति को अपनी निजी जानकारी साझा करनी पड़ती है। कुछ मामलों में तो बायोमेट्रिक पहचान अनिवार्य है, अगर वह तीसरे पक्ष के हाथ लग जाए तो और भी कई तरह के जोखिम पैदा हो सकते हैं। शीर्ष अदालत ने भी इस पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि गोपनीयता संबंधी शर्तें इतनी चालाकी से तैयार की जाती हैं कि आम व्यक्ति उन्हें समझ ही नहीं सकता। आज के तकनीकी दौर में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हर किसी के लिए एक जरूरत बन गया है। ऐसे में डिजिटल सुविधाओं ने भले ही हमारे कई कार्यों को आसान बना दिया है और सूचना के प्रवाह को तेज कर दिया है, लेकिन इससे उपजे खतरों में निजता की रक्षा का मसला भी गंभीर है। अब ज्यादातर हाथों में स्मार्ट मोबाइल है और इंटरनेट की सुलभता ने सोशल मीडिया तक पहुंच को आसान बना दिया है। मगर, डिजिटल साक्षरता के अभाव में बहुत कम लोग यह समझ रखते हैं कि सोशल मीडिया से जुड़ने के लिए वे जो निजी जानकारी संबंधित मंच के साथ साझा करते हैं, वह उनकी सहमति के बिना किसी तीसरे पक्ष को उपलब्ध कराई जा सकती है या उसका दुरुपयोग किया जा सकता है। इसी तरह के एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को 'मेटा प्लेटफार्म्स इंक' और 'वाट्सऐप' को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही कहा कि कोई भी कंपनी या मंच निजी जानकारी साझा करने के नाम पर नागरिकों की निजता के अधिकार से खिलवाड़ नहीं कर सकते।गौरतलब है कि आज एक मोबाइल नंबर लेने से लेकर बैंक में खाता खुलवाने तक, हर जगह संबंधित व्यक्ति को अपनी निजी जानकारी साझा करनी पड़ती है। कुछ मामलों में तो बायोमेट्रिक पहचान अनिवार्य है, अगर वह तीसरे पक्ष के हाथ लग जाए तो और भी कई तरह के जोखिम पैदा हो सकते हैं। यानी एक व्यक्ति की निजी जानकारी इतनी जगह चली जाती है कि वह तीसरे पक्ष के साथ कहां से साझा की गई, इसका पता लगाना भी मुश्किल हो जाता है। सोशल मीडिया मंच पर भी यह जोखिम बना रहता है, क्योंकि ज्यादातर उपयोगकर्ता उनके नियम-शर्तों से अनभिज्ञ होते हैं।शीर्ष अदालत ने भी इस पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि गोपनीयता संबंधी शर्तें इतनी चालाकी से तैयार की जाती हैं कि आम व्यक्ति उन्हें समझ ही नहीं सकता। यह निजी जानकारी की चोरी करने का एक सभ्य तरीका है और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। व्यक्तिगत पहचान सुनिश्चित करने और गैर कानूनी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए निजी जानकारी की जरूरत की दलील दी जाती है, लेकिन निजता के अधिकार का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।

महिलाओं और बेटियों के लिए घोषित योजनाएं-जैसे 'लखपति बिटिया योजना'-सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में सकारात्मक कदम मानी जा सकती हैं। यदि इन योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्रों तक पारदर्शिता से पहुंचता है, तो यह परिवारों की आर्थिक सुरक्षा और शिक्षा के अवसरों को बढ़ा सकता है। वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में दिल्ली के लिए 70 हजार करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि का प्रावधान केवल एक आर्थिक घोषणा नहीं, बल्कि राजधानी के भविष्य की रूपरेखा है। सड़क, रेल परिवहन, मेट्रो विस्तार, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रदूषण नियंत्रण और पुलिस व्यवस्था जैसे बुनियादी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान यह संकेत देता है कि केंद्र सरकार दिल्ली को एक सुव्यवस्थित, आधुनिक और आदर्श महानगर के रूप में विकसित करना चाहती है। ऐसे समय में जब दिल्ली की भाजपा सरकार अपना एक वर्ष पूर्ण कर रही है, यह स्वाभाविक है कि बीते वर्ष के कामकाज का मूल्यांकन किया जाए और देखा जाए कि तथाकथित ट्रिपल इंजन सरकार का लाभ दिल्लीवासियों को कितना और कैसे मिला है।

विकास का संकल्प- ट्रिपल इंजन से बदलेगी दिल्ली की तस्वीर

(ललित गर्ग)

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने कार्यकाल के एक वर्ष पूर्ण होने पर सरकार की उपलब्धियों और आगामी संकल्पों का उल्लेख करते हुए दावा किया कि उनकी सरकार ने न केवल नई योजनाओं की शुरुआत की, बल्कि पूर्ववर्ती सरकारों की लंबित और अधूरी परियोजनाओं को भी गति दी है। 'दिल्ली लखपति बिटिया योजना', मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, अधूरी पड़ी आधारभूत परियोजनाओं को पूरा करने की पहल, तथा महिलाओं और छात्रों के लिए नई राहतकारी योजनाओं का खाका-ये सब उनके पहले वर्ष के प्रमुख बिंदु रहे। उनका यह भी कहना है कि ट्रिपल इंजन की व्यवस्था-अर्थात केंद्र, राज्य और नगर निकाय में एक ही राजनीतिक नेतृत्व के कारण विकास कार्यों में समन्वय और गति दोनों आई है। ट्रिपल इंजन सरकार की अवधारणा का सबसे बड़ा लाभ वित्तीय समन्वय के रूप में सामने आया है। दिल्ली सरकार को अब पूंजीगत व्यय के लिए ऋण अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर उपलब्ध हो रहा है। पहले जहां ब्याज दर 13-14 प्रतिशत तक पहुंच जाती थी, वहीं अब लगभग सात प्रतिशत पर ऋण मिलना संभव हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा 21 हजार करोड़ रुपये तक की ऋण सीमा निर्धारित किए जाने से आधारभूत ढांचे के विकास में धनाभाव की आशंका कम हुई है। यही नहीं, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन तथा पीएम भीम योजना जैसी केंद्रीय योजनाओं की समयावधि बढ़वाने में भी दिल्ली सरकार को सफलता मिली है। आयुष्मान भारत जैसी जनकल्याणकारी योजना का लाभ अब राजधानी के अधिक से अधिक नागरिकों तक पहुंच रहा है, जिससे गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा की ठोस गारंटी मिल रही है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के संकेत अवश्य दिखाई दिए हैं। मोहल्ला क्लीनिक मॉडल पर उठे प्रश्नों और अधूरी स्वास्थ्य परियोजनाओं के बीच नई सरकार ने अस्पतालों के आधुनिकीकरण, बेड क्षमता बढ़ाने और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। यदि यह प्रयास निरंतरता से जारी रहा तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के अनुरूप विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी पारदर्शिता और गुणवत्ता सुधार का दावा किया गया है। पिछले वर्षों में शिक्षा मॉडल को लेकर जहां एक ओर प्रशंसा हुई, वहीं भवनों की गुणवत्ता, संसाधनों के उपयोग और परिणामों पर सवाल भी उठे। नई सरकार के लिए यह चुनौती है कि वह शिक्षा को राजनीतिक विमर्श से ऊपर उठाकर वास्तविक गुणवत्ता सुधार की दिशा में कार्य करे। परिवहन और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में भी गति लाने का प्रयास हुआ है। मेट्रो नेटवर्क के विस्तार, बस बेड़े के आधुनिकीकरण और सड़कों के सुधार की योजनाएं केंद्र और राज्य के समन्वय से आगे बढ़ रही हैं। दिल्ली मेट्रो पहले से ही राजधानी की

जीवनरेखा रही है, अब किराए में राहत या छात्रों के लिए विशेष प्रावधान जैसे कदम यदि लागू होते हैं तो इससे आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा। यातायात जाम की समस्या के समाधान के लिए फ्लाईओवर, अंडरपास और स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली पर ध्यान देना आवश्यक है। एक वर्ष में कुछ परियोजनाओं को गति मिली है, किंतु राजधानी जैसे विशाल महानगर में ठोस परिणामों के लिए निरंतर प्रयास अपेक्षित हैं।

सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण और वायु प्रदूषण की है। बीते दशक में दिल्ली विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में गिनी जाने लगी। यह केवल आंकड़ों का विषय नहीं, बल्कि जनस्वास्थ्य का संकट है। मुख्यमंत्री ने वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए ठोस योजनाओं का उल्लेख किया है-जैसे हरित आवरण बढ़ाना, निर्माण कार्यों पर निगरानी, सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहन और पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय। परंतु यह भी सत्य है कि प्रदूषण जैसी जटिल समस्या का समाधान केवल घोषणाओं से संभव नहीं, इसके लिए कठोर क्रियान्वयन, क्षेत्रीय सहयोग और जनसहभागिता की आवश्यकता होगी। यमुना की सफाई भी दिल्ली की अस्मिता से जुड़ा प्रश्न है। वर्षों से यमुना शुद्धिकरण के नाम पर योजनाएं बनती रहीं, बजट खर्च होता रहा, पर परिणाम संतोषजनक नहीं रहे। वर्तमान सरकार ने यमुना को स्वच्छ और पर्यटन योग्य बनाने का संकल्प दोहराया है। यदि सीवेज प्रबंधन, औद्योगिक अपशिष्ट नियंत्रण और नदी तट के पुनर्विकास की योजनाएं समयबद्ध तरीके से लागू होती हैं, तो यह दिल्ली की छवि को नया आयाम दे सकती हैं। यमुना का पुनर्जीवन केवल पर्यावरणीय मुद्दा नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक पुनरुत्थान का भी अवसर है।

महिलाओं और बेटियों के लिए घोषित योजनाएं-जैसे 'लखपति बिटिया योजना'-सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में सकारात्मक कदम मानी जा सकती हैं। यदि इन योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्रों तक पारदर्शिता से पहुंचता है, तो यह परिवारों की आर्थिक सुरक्षा और शिक्षा के अवसरों को बढ़ा सकता है। मुफ्त एलपीजी सिलेंडर जैसी पहल घरेलू अर्थव्यवस्था में राहत देती है, विशेषकर निम्न आय वर्ग के लिए। किंतु इन योजनाओं की सफलता क्रियान्वयन की गुणवत्ता पर निर्भर करेगी। एक वर्ष की अवधि किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ी नहीं होती, विशेषकर तब जब उसे पिछली सरकारों की अधूरी परियोजनाओं और व्यवस्थागत खामियों को भी दुरुस्त करना हो। यह भी सच है कि राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच विकास का वास्तविक आकलन कठिन हो जाता है। नई सरकार ने पूर्ववर्ती शासन की कमियों-जैसे कथित भ्रष्टाचार, अधूरी इमारतें, प्रदूषण नियंत्रण में विफलता को सुधारने का दावा किया है। किंतु जनता अब केवल आरोप नहीं, परिणाम देखना चाहती है। आने वाले वर्षों के लिए सरकार के सामने स्पष्ट लक्ष्य होने चाहिए-स्वच्छ वायु, स्वच्छ यमुना, सुगम यातायात, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य और पारदर्शी प्रशासन। राजधानी होने के नाते दिल्ली को केवल भारत का प्रशासनिक केंद्र नहीं, बल्कि आदर्श शहरी मॉडल बनना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि बजट में आवंटित राशि का पूर्ण और पारदर्शी उपयोग हो, परियोजनाएं समयबद्ध पूरी हों और जनभागीदारी को प्रोत्साहन मिले।

ट्रिपल इंजन सरकार का वास्तविक अर्थ तभी सिद्ध होगा जब समन्वय का लाभ जमीन पर दिखाई दे। केंद्र और राज्य के बीच टकराव की राजनीति के स्थान पर सहयोग की भावना यदि कायम रहती है, तो दिल्ली विकास की नई ऊंचाइयों को छू सकती है। एक वर्ष में कुछ सकारात्मक संकेत अवश्य मिले हैं, परंतु अभी लंबी यात्रा शेष है। सरकार को अपनी उपलब्धियों का प्रचार करने के साथ-साथ कमियों का ईमानदार आत्ममंथन भी करना होगा। दिल्ली की जनता जागरूक है और अपेक्षाएं भी बड़ी हैं। वह केवल वादों से संतुष्ट नहीं होगी, उसे परिणाम चाहिए। यदि रेखा गुप्ता सरकार अपने संकल्पों को धरातल पर उतारने में सफल होती है, तो आने वाले वर्षों में दिल्ली सचमुच एक स्वच्छ, स्वस्थ, सुरक्षित और आधुनिक महानगर के रूप में उभर सकती है। यही समय है जब बजट की घोषणाओं को विकास की वास्तविक कहानी में बदला जाए और राजधानी को समस्याओं के प्रतीक से समाधान के मॉडल में परिवर्तित किया जाए।(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

जो आज है, वह कल नहीं रहेगा

(सुंदरचंद ठाकुर)

जीवन का सबसे अनदेखा सत्य यह है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। जो अभी है, वह अगले ही क्षण बदलने की प्रक्रिया में है। फिर भी हम हर अनुभव को स्थायी मान लेते हैं। जो दुख अभी दिल पर रखा है, हमें लगता है वह हमेशा रहेगा। जो सुख अभी मिला है, हम चाहते हैं वह

कभी छिने नहीं। और इसी चाह और भय के बीच हम थकते रहते हैं। थोड़ा ठहर कर देखिए। पांच वर्ष पहले जो बात आपको तोड़ रही थी, आज वह स्मृति भर है। जिस व्यक्ति के जाने से जीवन रुकता हुआ लगा था, उसके बिना भी जीवन चल पड़ा। जिस असफलता ने आपको शर्मिंदा किया था, वही शायद आज आपकी परिपक्वता का कारण है। इसका अर्थ यह नहीं कि दुख छोटा था। उसका अर्थ केवल इतना है कि दुख भी स्थायी नहीं था।

मन की प्रकृति ही बदलना है। सुबह जो विचार आते हैं, शाम तक बदल जाते हैं। कभी बिना कारण खुशी, कभी बिना कारण उदासी। मन बादलों की तरह है। बादल आकाश में आते हैं, आकार लेते हैं, घिरते हैं, बरसते हैं और फिर छंट जाते हैं। लेकिन आकाश बना रहता है। समस्या तब शुरू होती है जब हम स्वयं को बादल मान लेते हैं और भूल जाते हैं कि हम आकाश भी हैं। सुख और दुख मन की अवस्थाएं हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं। पर हमारे भीतर एक ऐसी जगह है जो नहीं बदलती। वही साक्षी है। वही वह शांत केंद्र है जहां से हम अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को देख सकते हैं। जब कोई आपको अपमानित करता है, भीतर गुस्सा उठता है। जब कोई प्रशंसा करता है, भीतर प्रसन्नता उठती है। पर क्या आपने कभी यह देखा है कि इन दोनों को देखने वाला भी कोई है?

यदि आप केवल दो क्षण के लिए अपनी ही मनःस्थिति को देख लें, बिना उसमें डूबे हुए, तो एक अद्भुत स्वतंत्रता अनुभव होगी। जैसे आप नदी में नहीं, किनारे पर खड़े हों। नदी बहती रहेगी। लहरें उठेंगी। पर आप बहेंगे नहीं। यही साक्षी भाव है। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन से भाग जाना है। इसका अर्थ यह भी नहीं कि भावनाएं खत्म हो जाएंगी। भावनाएं आएंगी, क्योंकि वे मानव होने का स्वाभाविक हिस्सा हैं। अंतर केवल इतना होगा कि आप उनसे चिपकेंगे नहीं। आप जानेंगे कि यह भी बदलेगा। अभी जो भारी है, वह हल्का होगा। अभी जो सुखद है, वह भी बदल जाएगा।

जीवन का हर क्षण परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। यही उसका नियम है। इसी नियम को न समझने से पीड़ा जन्म लेती है। हम बदलती चीजों को पकड़कर स्थायी बनाना चाहते हैं। पर जीवन को पकड़ा नहीं जा सकता। उसे केवल जिया जा सकता है। जब आप साक्षी में टिकते हैं, तब एक अजीब शांति भीतर उतरती है। तब आप दुख में भी टूटते नहीं और सुख में भी बहकते नहीं। तब आप जीवन को उसके बदलते रंगों सहित स्वीकार करते हैं। जो आज है, वह कल नहीं रहेगा। पर जो देख रहा है, वह रहेगा। और वह आप ही तो हैं। और जब यह समझ भीतर उतर जाती है कि बदलना ही जीवन का स्वभाव है, तब शिकायतें कम होने लगती हैं। तब हम हर अनुभव को शिक्षक की तरह स्वीकारते हैं। तब हम पकड़ना छोड़ देते हैं और बहना सीख जाते हैं। और बहते हुए भी भीतर स्थिर रहना सीख जाते हैं। ऊपर व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं>

सिर्फ छाती में दर्द ही नहीं, डॉक्टर ने बताए ये पांच अजीब संकेत जिन्हें आप कर रहे हैं नज़रअंदाज

एमडी, कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. दिमित्री यारानोव ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट को शेयर करके दिल के रोगों से जुड़े कुछ लक्षण बताएं हैं जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जब दिल से जुड़ी बीमारी विकसित होती है, तो शरीर कुछ संकेत देने लगता है। सबसे सामान्य लक्षण सीने में दर्द या असहजता है, जो अक्सर बीच में या बाईं ओर महसूस होता है। बिगड़ती जीवनशैली और असंतुलित खानपान हृदय रोगों के खतरे को तेजी से बढ़ा रहे हैं। तला-भुना भोजन, अधिक नमक, ट्रांस फैट और जंक फूड का नियमित सेवन धमनियों में वसा जमा होने की प्रक्रिया को तेज करता है।

(साहना नूर)

शारीरिक गतिविधि की कमी, घंटों बैठकर काम करना, बढ़ता मोटापा, धूम्रपान और लगातार तनाव भी दिल की सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। हृदय रोगों के पीछे एक बड़ा कारण शरीर में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड स्तर है। जब खराब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल धमनियों की दीवारों पर जमने लगता है, तो ब्लॉकेज बनने का खतरा बढ़ जाता है। वहीं, ट्राइग्लिसराइड का उच्च स्तर रक्त को गाढ़ा बनाकर हृदय पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है। समय के साथ यह स्थिति हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है।

जब दिल से जुड़ी बीमारी विकसित होती है, तो शरीर कुछ संकेत देने लगता है। सबसे सामान्य लक्षण सीने में दर्द या असहजता है, जो अक्सर बीच में या बाईं ओर महसूस होता है। यह दर्द दबाव, जकड़न, भारीपन या जलन जैसा लग सकता है। कई बार ये दर्द कुछ मिनटों में ठीक हो जाता है, लेकिन कभी-कभी लंबे समय तक बना रह सकता है। एमडी, कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. दिमित्री यारानोव ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट को शेयर करके दिल के रोगों से जुड़े कुछ लक्षण बताएं हैं जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। डॉ. यारानोव ने हार्ट डिजीज के 5 सबसे अजीब और आमतौर पर नजरअंदाज किए जाने वाले चेतावनी संकेत साझा किए हैं, जो यह दर्शाते हैं कि आपका दिल किसी परेशानी में हो सकता है। आइए जानते हैं कि हार्ट अटैक के कौन-कौन से लक्षण है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं।

हार्ट अटैक के आमतौर पर दिखने वाले लक्षण

छाती में दर्द होना

सांस लेने में कठिनाई होना या सांस फूलना

बेचैनी या घबराहट का अनुभव

पसीना आना

मतली या उल्टी महसूस होना

चक्कर आना या बेहोशी जैसा लगना शामिल है।

जबड़े या दांतों में दर्द होना

कभी-कभी हार्ट अटैक का दर्द सिर्फ सीने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जबड़े, गर्दन, कंधे या दांतों तक फैल सकता है। कई लोग इसे दांतों की सामान्य समस्या समझकर अनदेखा कर देते हैं, जिससे जोखिम बढ़ जाता है। अगर जबड़े का दर्द अचानक शुरू हो, दबाव या जकड़न जैसा लगे और साथ में पसीना, घबराहट या सांस फूलना भी हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।

अत्यधिक थकान होना बिना ज्यादा शारीरिक मेहनत के असामान्य थकान महसूस होना दिल की कमजोरी का संकेत हो सकता है। यदि रोजमर्रा के छोटे काम, जैसे सीढ़ियां चढ़ना या चाय बनाना भी मुश्किल लगने लगे, तो यह सामान्य थकावट नहीं हो सकती। खासकर महिलाओं में हार्ट डिजीज का यह शुरुआती लक्षण माना जाता है। लगातार कमजोरी, चक्कर या सांस फूलने के साथ थकान हो तो चिकित्सकीय जांच कराना जरूरी है।

मसूड़ों में सूजन और दर्द: रिसर्च बताती है कि मसूड़ों की बीमारी, खासकर पीरियोडोंटाइटिस, का सीधा संबंध हृदय स्वास्थ्य से हो सकता है। मसूड़ों में सूजन, खून आना या दर्द केवल दंत समस्या नहीं है। बैक्टीरिया खून के जरिए दिल तक पहुंचकर सूजन बढ़ा सकते हैं और धमनियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए बार-बार

मसूड़ों में संक्रमण या सूजन दिखे तो डेंटल चेकअप के साथ हार्ट हेल्थ की जांच भी करानी चाहिए। **पैरों और टखनों में सूजन:** जब दिल प्रभावी ढंग से खून पंप नहीं कर पाता, तो शरीर के निचले हिस्सों जैसे पैर, टखने और पंजे में तरल पदार्थ जमा होने लगता है। इसे एडिमा कहा जाता है। यदि सूजन लगातार बनी रहे, जूते तंग लगने लगें या दबाने पर गड्ढा पड़ जाए, तो यह हार्ट फेल्योर का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में देरी किए बिना डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। खर्राटे और स्लीप एपनिया सोते समय तेज खर्राटे लेना या सांस का बार-बार रुकना स्लीप एपनिया का संकेत हो सकता है। यह स्थिति शरीर में ऑक्सीजन की कमी पैदा करती है और दिल पर अतिरिक्त दबाव डालती है। लंबे समय तक अनुपचारित रहने पर यह हाई ब्लड प्रेशर, अनियमित धड़कन और हार्ट डिजीज का जोखिम बढ़ा सकता है। यदि नींद के दौरान सांस रुकने, घुटन या दिन में अत्यधिक नींद आने की समस्या हो, तो जांच जरूरी है। (नोटःयह लेख केवल सामान्य जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें दी गई जानकारी चिकित्सा विशेषज्ञों या शोध रिपोर्टों पर आधारित हो सकती है, लेकिन यह किसी भी तरह से पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है।

विकसित छत्तीसगढ़ की नींव रखने वाला दूरदर्शी बजट

बस्तर/मूक पत्रिका

छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रस्तुत वर्ष 2026-27 के राज्य बजट को लेकर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष जी.वेंकट ने इसे विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में ऐतिहासिक और दूरदर्शी बजट बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज़ नहीं, बल्कि प्रदेश को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाने का स्पष्ट रोडमैप है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि बजट में माताओं-बहनों, बेटियों, युवाओं, किसानों, श्रमिकों और आदिवासी समाज सभी के हितों को प्राथमिकता दी गई है। रायपुर में मेट्रो-होम्योपैथी अस्पताल की स्थापना, महिलाओं के लिए रजिस्ट्री शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट, बेटियों के 18 वर्ष पूर्ण करने पर आर्थिक सहायता जैसी घोषणाएं महिला सशक्तिकरण को नई गति देंगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा और युवाओं के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। छात्र-छात्राओं के लिए हॉस्टल सुविधा का विस्तार, एजुकेशन सिटी की परिकल्पना, स्किल डेवलपमेंट और रोजगारोन्मुखी योजनाएं युवाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगी।

युवाओं के स्टार्ट-अप और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए की गई वित्तीय घोषणाएं भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर की गई हैं। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि बजट में आदिवासी अंचलों, विशेषकर बस्तर और सरगुजा जैसे पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इन क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सड़कों और कनेक्टिविटी पर 2024 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। दूर-दराज़ और अंदरूनी इलाकों को राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों से जोड़ने, पुल-पुलियों के निर्माण, सिंचाई, बिजली और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए बड़े प्रावधान यह दर्शाते हैं कि सरकार संतुलित और समावेशी विकास के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

नगरीय विकास की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि रायपुर में मेट्रो परियोजना, शहरी अधोसंरचना के विस्तार, ट्रैफिक और परिवहन सुधार तथा आवास योजनाओं के लिए बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। इससे शहरों को आधुनिक स्वरूप मिलेगा और आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि औद्योगिक विकास, निवेश प्रोत्साहन और रोजगार सृजन पर केंद्रित बजट प्रावधान छत्तीसगढ़ को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएंगे। किसानों के लिए सिंचाई परियोजनाओं, कृषि अवसंरचना और ग्रामीण विकास पर बढ़ा हुआ खर्च ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देगा।

उन्होंने विश्वास जताया कि यह बजट ज्ञान, गति और संकल्प के साथ छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने वाला बजट है।

आने वाले वर्षों में इसके सकारात्मक परिणाम ज़मीन पर स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। अंत में उन्होंने कहा कि यह बजट वास्तव में विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करने वाला बजट है।

युवा शक्ति को समर्पित यह बजट, सुकमा का ख्याल प्रदेश भी खुशहाल- शोभन

सुकमा/मूक पत्रिका

प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2026ङ्क27 के बजट का युवाओ के लिए, बस्तर के विकास, विश्वास और विस्तार के लिए स्वागत करने योग्य है। इस वर्ष का बजट संकल्प की थीम पर आधारित रहा संकल्प यह दर्शाता है कि सरकार केवल नीतियां बनाने तक सीमित नहीं है बल्कि उन्हें जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू करने के लिए संकल्पित है। भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष शोभन गद्दामी ने कहा कि यह बजट राज्य के समग्र और संतुलित विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि बजट में किसान, महिला, युवा, गरीब, आदिवासी समाज, श्रमिक, व्यापारी और मध्यम वर्ग के हितों को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पेयजल, रोजगार, उद्योग और ग्रामीण विकास से जुड़े क्षेत्रों को विशेष महत्व दिया गया है, जिससे राज्य की विकास गति और तेज होगी। जिला अध्यक्ष शोभन ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस बजट में सुकमा का विशेष ध्यान रखा गया है नक्सलवाद से आजादी के बाद अब जगरगुण्डा कि तस्वीर बदलेंगी यहां एजुकेशन सिटी स्थापना के लिए करोड़ों रुपये का प्रावधान दिया गया यह सुकमा के विकास और नक्सलगढ के बच्चों के लिए निव साबित होगा । इसका उद्देश्य तथाकथित नक्सलवाद के गढ़ कहे जाने वाले जगरगुंडा को शिक्षा के केन्द्र बिन्दु के रूप में विकसित करना है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा और विद्यार्थियों को आधुनिक शैक्षणिक संसाधनों का लाभ मिलेगा। ग्रामीणों की माँग पर कुन्ना से मिचवार में पुल निर्माण कार्य परियोजना के लिए 7 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे रोड कनेक्टिविटी को नई दिशा मिलेगी और बरसात के दिनों में भी ग्रामीण आवागमन कर सकेंगे। खेल अधोसंरचना विकास के अंतर्गत स्टेडियम निर्माण के लिए सुकमा जिले का भी चयन किया गया है। यह बजट जिले को विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भाजयुमो अध्यक्ष शोभन ने बताया कि विकसित छत्तीसगढ़ के विजन डॉक्यूमेंट छत्तीसगढ़ अंजर 2037 के लक्ष्य की पूर्ति एवं राज्य की सतत विकास यात्रा में उठाया गया एक कदम है बजट में पांच नए मिशन भी शामिल किए गए यह एक संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है जहां आर्थिक विस्तार सामाजिक न्याय आधारभूत संरचना निर्माण और सांस्कृतिक पहचान सभी एक साथ आगे बढ़े।

छत्तीसगढ़ बजट पर कांग्रेस का हमलाः जनविरोधी और जुमलों का पुलिंदाः राजेंद्र प्रसाद भगत

बलरामपुर/कुसमी/ मूक पत्रिका

नगर पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद भगत ने छत्तीसगढ़ में पेश किए गए ताज़ा बजट को आम जनता के साथ छलावा बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह बजट महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं पर ठोस समाधान देने में पूरी तरह विफल रहा है।

नगर पंचायत अध्यक्ष भगत ने आरोप लगाया कि- सरकार ने बड़े-बड़े वादों और आंकड़ों के सहारे बजट को आकर्षक दिखाने की कोशिश की है, लेकिन जमीनी स्तर पर आम लोगों को कोई वास्तविक राहत नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार सृजन, किसानों के लिए समर्थन मूल्य और कर्ज राहत, तथा गरीब एवं मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए राहत संबंधी प्रावधान बजट में स्पष्ट और प्रभावी रूप से दिखाई नहीं देते।

भगत ने यह भी कहा कि नगर निकायों-और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किए गए हैं। ग्रामीण सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं पर बजट में अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया। सरकार को चाहिए था कि वह गांव, किसान और गरीब को केंद्र में रखकर बजट बनाती, उन्होंने कहा। कांग्रेस नेता ने मांग की कि सरकार बजट में आवश्यक संशोधन कर जनता की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप प्रावधान सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनहित के मुद्दों को लेकर सड़क से सदन तक संघर्ष जारी ।

प्रदेश नेतृत्व के भरोसे पर प्रीतम गुप्ता बने भाजयुमो –जिला उपाध्यक्ष

सामरी–गोपातु के युवा चेहरे को बड़ी जिम्मेदारी, प्रीतम गुप्ता को मिला जिला उपाध्यक्ष पद

बलरामपुर-रामानुजगंज/ मूक पत्रिका

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष माo किरण सिंह देव जी एवं प्रदेश संगठन महामंत्री माo पवन साय जी के मार्गदर्शन में व युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष माo राहुल टिकरिया जी के निर्देशानुसार एवं भाजपा जिलाध्यक्ष माo ओमप्रकाश जायसवाल जी के अनुशंसा से युवा मोर्चा जिला पदाधिकारी एवं कार्यसमिति सदस्य की घोषणा की जाती है, जो निम्नानुसार है :-

क्र.	दायित्व	नाम	मोबाईल नं.	पता
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	उपाध्यक्ष	श्री प्रितम गुप्ता	9399774293	गोपातु
3	उपाध्यक्ष	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	उपाध्यक्ष	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	उपाध्यक्ष	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	महामंत्री	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	महामंत्री	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	मंत्री	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	मंत्री	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	मंत्री	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	मंत्री	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	मंत्री	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	मंत्री	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	कोषाध्यक्ष	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	सह कोषाध्यक्ष	[illegible]	[illegible]	[illegible]

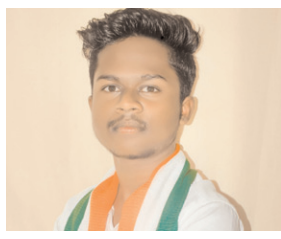

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष किरण सिंह देव एवं प्रदेश संगठन महामंत्री साय के मार्गदर्शन में तथा युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष राहुल टिकरिया के निर्देशानुसार और भाजपा जिला अध्यक्ष ओमप्रकाश जयसवाल की अनुशंसा पर भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला पदाधिकारी एवं कार्यसमिति सदस्यों की घोषणा की गई। घोषणा के तहत कुसमी विकासखंड के गोपातु सामरी निवासी युवा नेता प्रीतम गुप्ता को जिला उपाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है। संगठन ने उनके लंबे राजनीतिक अनुभव और सक्रिय भूमिका को देखते हुए यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। प्रीतम गुप्ता पूर्व में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कुसमी के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी मंडल कुसमी के मंत्री, भाजपा युवा मोर्चा मंडल कुसमी के अध्यक्ष सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर दायित्व निभा चुके हैं। वर्तमान में वे सामरी हाई स्कूल में सांसद प्रतिनिधि के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। संगठन के वरिष्ठ नेताओं ने विश्वास जताया है कि प्रीतम गुप्ता अपने अनुभव और नेतृत्व क्षमता से युवा मोर्चा को और मजबूत करेंगे तथा पार्टी की नीतियों को गांव-गांव तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएंगे। उनकी नियुक्ति से कुसमी एवं सामरी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है और समर्थकों ने उन्हें बधाई दी है।

22 वर्ष की उम्र में बड़ी जिम्मेदारी, गोविन्द कश्यप बने बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव

बस्तर /मूक पत्रिका

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी नियुक्ति आदेश के तहत 22 वर्षीय गोविन्द कश्यप को बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी का सचिव नियुक्त किया गया है। कम उम्र में मिली इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जबरदस्त उत्साह तथा नई ऊर्जा का संचार हुआ है। गोविन्द कश्यप इससे पूर्व भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) सोशल मीडिया विभाग में जिला चेयरमैन की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। छात्र राजनीति के दौरान उन्होंने संगठन को डिजिटल रूप से मजबूत किया और युवाओं को कांग्रेस विचारधारा से जोड़ने में सक्रिय योगदान दिया। उन्होंने कहा कि इतनी कम उम्र में मिली इस बड़ी जिम्मेदारी को वे निस्वार्थ भाव, निष्ठा, ईमानदारी और पूर्ण समर्पण के साथ निभाएंगे। गांव-गांव जाकर संगठन को मजबूत करेंगे तथा आम जनता की आवाज को पार्टी मंच तक प्रभावी ढंग से पहुंचाएंगे। गोविन्द कश्यप के क्षेत्र के जमीनी स्तर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी और गर्व का माहौल है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि गोविन्द कश्यप पढ़े-लिखे, शिक्षित, सक्रिय और जुझारू युवा नेता हैं, जिनके नेतृत्व में संगठन को नई दिशा और मजबूती मिलेगी।

जगरगुंडा बनेगा एजुकेशन सिटी, सरपंच ने जताया आभार

जगरगुंडा/मूक पत्रिका

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य बजट में जगरगुंडा को एजुकेशन सिटी के रूप में विकसित करने की ऐतिहासिक घोषणा से क्षेत्र में उत्साह और नई उम्मीद का माहौल है। वर्षो तक विकास की मुख्यधारा से दूर रहे इस क्षेत्र को अब शिक्षा के बड़े केंद्र के रूप में विकसित किए जाने की पहल ने स्थानीय नागरिकों में खुशी की लहर पैदा कर दी है। इस घोषणा को केवल एक योजना नहीं, बल्कि क्षेत्र के लोगों के लंबे समय से संजोए सपनों को साकार करने की दिशा में ठोस कदम माना जा रहा है। शिक्षा को समाज के सर्वांगीण विकास की आधारशिला बताते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कहा कि एजुकेशन सिटी की स्थापना से बच्चों और युवाओं को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं, आधुनिक संसाधन और उज्ज्वल भविष्य के अवसर मिलेंगे। जगरगुंडा की सरपंच नित्या कोसमा ने राज्य शासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस पहल से न केवल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और आधारभूत संरचना के विकास को भी गति मिलेगी। गौरतलब है कि जगरगुंडा क्षेत्र लंबे समय तक बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझता रहा है। ऐसे में एजुकेशन सिटी की स्थापना से सामाजिक और आर्थिक बदलाव की नई संभावनाएं खुलेंगी। स्थानीय नागरिकों को विश्वास है कि आने वाले समय में जगरगुंडा प्रदेश में शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में अपनी पहचान स्थापित करेगा।

सुकमा में क्रेडा कर्मियों का आरोप ,वेतन मांगने पर 8 कर्मचारियों की सेवामुक्ति सुकमा

सुकमा/मूक पत्रिका

छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) सुकमा में कार्यरत 8 सेवाकर्ता (क्लस्टर टेक्नीशियन) कर्मचारियों ने विभागीय अधिकारियों पर आर्थिक शोषण, अवैध वेतन कटौती एवं द्वेषपूर्ण सेवामुक्ति के गंभीर आरोप लगाए हैं।

15 माह से वेतन भुगतान में अनियमितता

क्लस्टर टेक्नीशियनों का कहना है कि पिछले लगभग 15 महीनों से वेतन का नियमित भुगतान नहीं किया जा रहा है। वर्तमान में दिसंबर माह से अभी तक का वेतन लंबित बताया गया है, जिससे अनेक परिवार आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं।कर्मचारियों के अनुसार वे दुर्गम एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। विगत कई वर्षों से वे राज्य की विभिन्न सौर ऊर्जा योजनाओं के संचालन, संधारण, रखरखाव एवं मॉनिटरिंग का कार्य पूर्ण निष्ठा एवं जिम्मेदारी के साथ करते आ रहे हैं, बावजूद इसके उन्हें अब तक स्थायी सेवा सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है।

वेतन कटौती और प्रताड़ना के आरोप

पीड़ित कर्मचारियों का आरोप है कि वेतन भुगतान में 3ङ्क4 माह तक की देरी की जाती रही तथा प्रतिमाह ?7,000 से ?8,000 तक की कटौती की गई।उनका कहना है कि जब उन्होंने लंबित वेतन के भुगतान की मांग की, तो विभागीय अधिकारियों द्वारा बदले की भावना से 8 कर्मचारियों को बिना कारण बताओ नोटिस एवं बिना वैधानिक प्रक्रिया अपनाए सेवा से पृथक कर दिया गया।बताया जा रहा है कि सेवामुक्ति आदेश पर विभागीय अधिकारियों के हस्ताक्षर हैं, किंतु संबंधित अधिकारी इस संबंध में अनभिज्ञता जता रहे हैं, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है।

प्रशासन से न्याय की मांग

पीड़ित कर्मचारियों ने इस संबंध में जिला कलेक्टर तथा थाना सुकमा में शिकायत दर्ज कराते हुए निष्पक्ष जांच, अवैध वेतन कटौती की राशि की वापसी एवं सेवा बहाली की मांग की है।कर्मचारियों का कहना है कि लगातार वेतन कटौती और सेवा समाप्ति के कारण उनके परिवार गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से शीघ्र हस्तक्षेप कर न्याय दिलाने की अपील की है। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया गया, किंतु समाचार लिखे जाने तक उनका पक्ष प्राप्त नहीं हो सका।

छत्तीसगढ़ बजट 2026 पर कांग्रेस का वारः आम लोगों के हक में नहीं, सिर्फ आंकड़ों का खेलः हरीश मिश्रा

कुसमी/मूक पत्रिका

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पेश किए गए वर्ष 2026-27 के बजट पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

कुसमी कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष हरीश मिश्रा ने कहा- कि यह बजट आम जनता के हक में नहीं है, बल्कि केवल घोषणाओं और आंकड़ों का खेल है। भगत ने कहा कि बजट में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, अधोसंरचना और युवाओं के लिए रोजगार जैसी कई मदों में बड़ी-बड़ी घोषणाएं की गई हैं, लेकिन जमीनी हकीकत से इसका कोई सीधा संबंध नहीं दिखता।

उन्होंने उल्लेख किया कि— कृषि क्षेत्र के लिए अनुदान और योजनाओं की घोषणा तो की गई है, परंतु किसानों को समर्थन मूल्य, बोनस और कर्ज राहत पर स्पष्ट प्रावधान नहीं दिखते।

युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार सृजन की बात कही गई है, लेकिन स्थायी सरकारी नौकरियों पर कोई ठोस निर्णय नहीं है। स्वास्थ्य और शिक्षा बजट में बढ़ोतरी का दावा किया गया है, मगर ग्रामीण अस्पतालों और स्कूलों की स्थिति सुधारने की स्पष्ट कार्ययोजना नजर नहीं आती। नगर निकायों और पंचायतों के विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय आवंटन का अभाव है।

मिश्रा ने कहा- सरकार ने बजट में बड़ी योजनाओं का प्रचार तो किया है, लेकिन महंगाई से जूझ रही जनता को राहत देने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए। आम लोगों के हक, किसान की आय, बेरोजगार युवाओं के भविष्य और गरीब परिवारों की सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं दी गई। उन्होंने मांग की कि सरकार बजट में संशोधन कर वास्तविक जनहितकारी प्रावधान जोड़े, ताकि प्रदेश के ग्रामीण और शहरी दोनों वर्गों को सीधा लाभ मिल सके। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को जनता के बीच लेकर जाएगी और आवश्यक हुआ तो आंदोलन भी ।

आयुष्मान योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए

विकसित भारत 2047 की ओर छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक बजट : धनीराम बारसे

सुकमा/मूक पत्रिका

छत्तीसगढ़ की विष्णु देव वाली सुशासन सरकार के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया, तथा चौधरी के प्रस्तुत बजट को छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद से अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है, तो वहीं इस बजट में प्रदेश के सर्वे वर्ग के लिए सरकार ने जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रावधान किया है। इस बजट को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष धनीराम बारसे ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने आज राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश करते हुए विकास की नई दिशा तय की हैं । बजट में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधानों के साथ राजधानी रायपुर को आधुनिक और स्मार्ट बनाने हेतु मेट्रो रेल सर्वे तथा ॣढ्ढ सेंटर जैसी बड़ी घोषणाएं की गई हैं।

श्री बारसे ने कहा कि वित्त मंत्री ने बस्तर क्षेत्र के अबूझमाड़ और जगरगुंडा में दो नई एजुकेशन सिटी की स्थापना को मंजूरी दी, जिसके लिए ?100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। भानुप्रतापपुर कालेज भवन निर्माण के लिये भी बजट में राशि दी गई है ।नगर पालिका और नगर पंचायत उत्थान के लिए मुख्यमंत्री आदर्श योजना के लिए 200 करोड़, प्रधानमंत्री आवास के लिए 800 करोड़, 4 लाइब्रेरी के लिए 22 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है, सूर्य घर योजना के लिए केंद्रीय अनुदान के अतिरिक्त 400 करोड़ रुपए, 5 नालंदा परिसरों के निर्माण के लिए 22 करोड़ रुपए ,500 आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए 42 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है । इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी व वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी का धन्यवाद।। भाजपा जिला अध्यक्ष धनीराम बारसे ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य और तकनीक पर विशेष फोकस रखते हुए आयुष्मान योजना के लिए ?1500 करोड़,मितानिनों के लिए ?350 करोड़ की कल्याण निधि,मेकाहारा में ॣढ्ढ (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) आधारित स्वास्थ्य सेवाओं हेतु ?10 करोड़ रुपये, तथा कांकेर में नर्सिंग कालेज खोलने हेतु बजट में प्रावधान किया है।

जिला अध्यक्ष धनीराम बारसे ने कहा कि शिक्षा के लिये सेंटर ऑफएक्सीलेंस 5 सरकारी कॉलेजों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए 15 करोड़। कोचिंग सहायता ह्वश्वस्रञ्ज और ष्टस्नस्न की तैयारी के लिए 35 करोड़ की आर्थिक मदद। मेगा परीक्षा केंद्र प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 25 करोड़ से परीक्षा केंद्रों की स्थापना। उच्च शिक्षा विश्वविद्यालयों के लिए 731 करोड़ और कॉलेज भवनों के लिए 25 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया है।श्री बारसे ने बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि छग का बजट सर्व समाज के विकास को नई दिशा देने वाला बजट है । भाजपा हमेशा जनता के विकास के लिये सोचती भी है और करती भी है । श्री बारसे ने कहा कि खाद्यान्न योजना मुफ्त चावल और अन्य राशन के लिए 5000 करोड़। पीएम आवास गरीबों के घर के लिए 800 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान।सौर ऊर्जा सूर्य घर योजना के लिए 400 करोड़ की राशि।पेंशन विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के लिए 1422 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है । भाजपा जिला अध्यक्ष धनीराम बारसे ने बजट को महिलाओं के उत्थान की दिशा में उठाया गया कदम बताते हुए कहा कि मितानिन कल्याण मितानिनों के लिए 350 करोड़ की कल्याण निधि। पर्यटन बस्तर में होम स्टे और मैनपाट के विकास हेतु विशेष फंड का प्रावधान किया गया है।

आयुष्मान योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए । मुख्यमंत्री दुरुतगामी सड़क संपर्क योजना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान । छत्तीसगढ़ में 75 करोड़ की राशि से 250 महतारी सदन बनेंगे.। श्री बारसे ने बजट के बारे में बोलते हुए कहा कि यह बजट छत्तीसगढ़ को तकनीकी, शैक्षिक और बुनियादी रूप से सशक्त बनाएगा। रायपुर में मेट्रो रेल सर्वे और ॣढ्ढ सेंटर की स्थापना राज्य को आधुनिक राज्यों की कतार में खड़ा करने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है, जबकि बस्तर-सरगुजा क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान वहां के युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने में मदद करेंगेश्री बारसे ने बजट को जनहितकारी बताते कहा कि किसानों की चिंता इस सरकार ने की है । इंद्रावती नदी पर लगभग ?2400 करोड़ की लागत से बैराज निर्माण का निर्णय किसानों और जल प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथ ही कांकेर जिले के मेढ़की नदी पर बैराज का निर्माण किसानों की फसलों को पूरे बारह माह सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराएगा । सबसे बड़ा बजट जल संसाधन विभाग के लिए 3500 करोड़ आवंटित हुआ है। ग्रामीण कनेक्टिविटी 206 गांवों को शहरों से जोड़ने के लिए 250 करोड़ इस बजट में दिया गया है ।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आधार सीडिंग एवं बैंक खाता सुधार के निर्देश, 7 दिवस के भीतर त्रुटि सुधार करना अनिवार्य

बेमेतरा/मूक पत्रिका

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कॉलेज स्तर) अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2025-26 की छात्रवृत्ति राशि अब आधार सीडिंग किए गए बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की जा रही है।जिले के ऐसे विद्यार्थी, जिनकी छात्रवृत्ति आधार सीडिंग इनएक्टिव होने, बैंक खाता क्रमांक त्रुटिपूर्ण होने अथवा बैंक खाता बंद होने के कारण प्राप्त नहीं हो पाई है, वे तत्काल अपने स्टूडेंट आईडी के माध्यम से ऑनलाइन त्रुटि सुधार करें। विद्यार्थियों को निर्देशित किया गया है कि वे आधार से लिंक (सीडिंग) किए गए सही एवं सक्रिय बैंक खाते की प्रविष्टि आगामी 07 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। निर्धारित समयावधि में त्रुटि सुधार नहीं किए जाने की स्थिति में छात्रवृत्ति राशि प्राप्त नहीं होने पर संपूर्ण जवाबदारी संबंधित विद्यार्थी की होगी। किसी भी प्रकार की समस्या या मार्गदर्शन हेतु विद्यार्थी अपनी अध्ययनरत संस्था के छात्रवृत्ति प्रभारी से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, बेमेतरा (कलेक्टोरेट परिसर, कक्ष क्रमांक-71, छात्रवृत्ति शाखा) में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। प्रशासन ने सभी पात्र विद्यार्थियों से समयसीमा के भीतर आवश्यक सुधार कर छात्रवृत्ति का लाभ सुनिश्चित करने की अपील की है।

संक्षिप्त समाचार

सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने आज अपने गैलेक्सी इकोसिस्टम में गैलेक्सी एआई का विस्तार किया

नईदिल्ली। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने आज अपने गैलेक्सी इकोसिस्टम में गैलेक्सी एआई का विस्तार करते हुए 'मल्टी-एजेंट इकोसिस्टम' को और मजबूत करने की घोषणा की है। कंपनी का उद्देश्य यूज़र्स को अधिक विकल्प, और बेहतर नियंत्रण देना है, ताकि वे अपने दैनिक कार्य कम मेहनत और अधिक स्वाभाविक तरीके से पूरे कर सकें। कंपनी के अनुसार, अब लोग अलग-अलग कामों के लिए कई तरह के एआई एजेंट्स का उपयोग कर रहे हैं। हालिया आंकड़ों के मुताबिक, 10 में से लगभग 8 यूज़र्स दो या उससे अधिक एआई एजेंट्स पर निर्भर हैं। इसी बदलाव को देखते हुए, सैमसंग गैलेक्सी एआई को इस तरह विकसित कर रहा है कि यूज़र अपनी पसंद और जरूरत के हिसाब से अलग-अलग इंटीग्रेटेड एआई अनुभवों को चुन सकें। गैलेक्सी एआई को ऑपरेटिंग सिस्टम के स्तर पर गहराई से जोड़ा गया है। यह केवल किसी एक ऐप तक सीमित रहने के बजाय पूरे डिवाइस के सिस्टम लेवल पर काम करता है। यह यूज़र की जरूरतों को समझते हुए ज्यादा स्वाभाविक और सरल इंटरैक्शन सुनिश्चित करता है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के मोबाइल एक्सपीरियंस (एमएक्स) बिजनेस के प्रेसिडेंट और आर एंड डी हेड, वॉन-जून चोई ने कहा, हम एक खुले और समावेशी एआई इकोसिस्टम के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो यूज़र्स को जटिल कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए अधिक विकल्प और नियंत्रण दे। गैलेक्सी AI एक ऑर्केस्ट्रेटर (सूत्रधार) की तरह काम करता है, जो विभिन्न एआई क्षमताओं को जोड़कर एक सहज और एकीकृत अनुभव प्रदान करता है।

कलर्स के 'लाफ्टर शेफ़्स अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट' में वाइल्ड कुकिंग के जंगल में आपका स्वागत है!

कलर्स के शो 'लाफ्टर शेफ़्स अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट' की किचन इस बार जंगल थीम में तब्दील हो गई, जहां कुकिंग का हंगामा हंसी से भरे सफ़री में बदल गया। एप्रन की जगह जानवरों के अंदाज़ ने ली और किचन का फ्लोर जंगल में बदल गया, जहां सिर्फएक ही नियम था–हंसो या हंसाओ! जंगल स्पेशल एपिसोड में प्रतिभागियों ने अपने वाइल्ड अंदाज़ को अपनाया अंकिता लोखंडे बिल्ली बनकर मंच पर आई, सुधेश लेहरी जंगल सफ़री गार्ड के रूप में नज़र आए, जन्नत जुबैर ने केंचुए का किरदार निभाया, कृष्णा ऊँट बने, सामर्थ घोड़े के रूप में आए, भारती तितली की तरह इधर-उधर उड़ती दिखीं, जबकि बाकी टीम भी उतने ही मज़ेदार और अनोखे अवतारों में दिखाई दी। इस वाइल्ड मस्ती में क्यूटनेस का तड़का तब लगा जब कंटेस्टेंट्स अपने असली पालतू जानवरों को लेकर पहुंचे। करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश अपने डॉग्स मज़नू और डाकू को लेकर आए, अंकिता ने अपनी बिल्ली माऊ से सबको मिलवाया, अर्जुन बिजलानी अपनी कैट ऑरा के साथ आए, जबकि अली गोनी अपने डॉग रैम्बो को लेकर पहुंचे। कुछ देर के लिए किचन पालतू जानवरों का पैराडाइज़ बन गई और दिल पिघल गए, भले ही काउंटर पर कुकिंग का हंगामा जारी रहा।

प्रोजेक्ट्स टुडे ने भारत के परियोजना इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एआई-संचालित व्यावसायिक अवसर प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया

नईदिल्ली। प्रोजेक्ट्स टुडे ने भारत के परियोजना इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एआई-संचालित व्यावसायिक अवसर प्लेटफॉर्म का अनावरण किया। यह नया प्लेटफॉर्म परियोजना जीवनचक्र संदर्भ, निविदाएं और एल1/आदेश अपडेट, तथा हितधारकों की जानकारी को एक सुविधाजनक कार्यप्रणाली में एकीकृत करता है जिससे संगठनों को सही समय पर सही परियोजनाओं से जुड़ने में मदद मिलती है। उन्नत प्लेटफॉर्म व्यावहारिक परिणामों पर केंद्रित एआई-सक्षम विकास प्रस्तुत करता है, जिसमें बीओक्यू खोज, उप-परियोजना ट्रैकिंग, निविदा से आदेश तक की यात्रा की विजिबिलिटी, बोलीदाता और भागीदारी अंतर्दृष्टि, अवसर अनुमान उपकरण, विश्वसनीयता और विश्लेषण डैशबोर्ड तथा हितधारकों के साथ बेहतर संबंध मानचित्रण शामिल हैं। ये क्षमताएं यूजर्स की आवश्यकताओं के आधार पर प्रासंगिक अवसरों की तेजी से खोज को सक्षम बनाती हैं। संगठनों को चरण, दायरे और हितधारकों के बारे में स्पष्ट संदर्भ के साथ क्या हो रहा है से हमें आगे क्या करना चाहिए की ओर बढ़ने में मदद करती हैं। 25 से अधिक वर्षों के रिसर्च-आधारित कवरेज के साथ प्रोजेक्ट्स टुडे 50,000 से अधिक सक्रिय परियोजनाओं पर नजर रखता है जो वर्तमान में गंभीर विचार-विमर्श, योजना, निविदा प्रक्रिया या कार्यान्वयन के चरण में हैं। यह प्लेटफ़ॉर्म हर महीने 1,500 से अधिक नई परियोजनाओं और 10,000 से अधिक निविदाओं के साथ 1,200 से अधिक मासिक एल1/आदेश अपडेट को कैप्चर करता है जो विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों में निर्णय लेने में सहायक होता है।

एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट पशु विकास दिवस के माध्यम से सर्वोत्तम सेवा में अग्रणी

1.55 लाख ग्रामीणों पर उत्पन्न किया सकारात्मक प्रभाव

बिलासपुर । भारत की अग्रणी एनबीएफसी में से एक एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट ने 14 फरवरी 2026 को अपनी प्रमुख पशु कल्याण एवं ग्रामीण आजीविका पहल, पशु विकास दिवस के आठवें संस्करण का सफल समापन किया। 'सर्वोत्तम सेवा: पशु, परिवार और प्रगति' की थीम पर आधारित इस पहल ने पशुओं के स्वास्थ्य, परिवार के कल्याण एवं स्थायी प्रगति को बढ़ावा देकर समग्र ग्रामीण विकास के लिए संगठन की प्रतिबद्धता को मजबूत बनाया।

इस पहल के सफल समापन पर बात करते हुए श्री रवि नारायणन, मैनेजिंग डायरेक्टर एवं चीफ़ एक्ज़क्टिव ऑफ़िसर, एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट ने कहा, ''सर्वोत्तम सेवा सर्वोच्च मानकों की सेवाएं उपलब्ध कराने के बारे में है- जहां सहानुभूति के साथ प्रभाव और इरादे का संयोजन गहरा प्रभाव उत्पन्न करता है। ग्रामीण भारत में पशुओं का स्वास्थ्य, परिवारों की सुरक्षा और आर्थिक प्रगति एक दूसरे के साथ गहराई से जुड़े हैं। पशु विकास दिवस पशुओं की देखभाल, आजीविका के सशक्तीकरण और समुदायों के कल्याण को समर्थन देकर इस सिस्टम को मजबूत बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस पहल के ज़रिए हमारा उद्देश्य ऐसे स्थायी परिणामों का निर्माण करना है जो किसान के परिवार को सशक्त बनाएं और बुनियादी स्तर पर समावेशी विकास को बढ़ावा दें।'' 2014 में लॉन्च किया गया पशु विकास दिवस पशु मालिकों को नि:शुल्क वेटेरीनेरी सेवाएं और विशेषज्ञों का मार्गदर्शन उपलब्ध कराकर उनकी स्वास्थ्यसेवा संबंधी ज़रूरतों को पूरा करता है। पिछले सालों के दौरान यह पहल देश के सबसे बड़े एक दिवसीय पशु कल्याण प्रोग्रामों में से एक के रूप में उभरी है। एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट ने 1.55 लाख से अधिक ज़िंदगियों पर सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न किया है, जिसके तहत तकरीबन 1.4 लाख पशुओं का इलाज किया गया, 14,000 से अधिक लोगों को स्वास्थ्यसेवाओं में सहयोग दिया गया, इससे 30,000 से अधिक परिवारों को लाभ हुआ। इस पहल का संचालन 16 राज्यों में 510 एसएमएफजी ग्रामशक्ति शाखाओं में किया गया, जो ग्रामीण भारत में कंपनी की गहरी पहुंच को दर्शाता है।

छत्तीसगढ़ में पशु विकास दिवस का आयोजन 17 लोकेशनों में किया गया, जिसके तहत तकरीबन 4000 पशुओं को स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं मुहैया कराई गईं और 650 से अधिक परिवारों को लाभ हुआ। हर कैम्प में स्थानीय वेटेरीनेरी डॉक्टरों ने पशुओं की नि:शुल्क जांच की, पशुओं के लिए मुफ्त दवाएं बांटी गईं, टीकाकरण किया और दुधारू पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सलाह दी गई। पिछले सालों के दौरान इस पहल को कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं जो इसके प्रभाव और पैमाने की पुष्टि करते हैं। पीवीडी को 2015 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, 2018 में बेस्ट ऑफइंडिया रिकॉर्ड्स में, 2019 में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में तथा 2024 में एक ही दिन में सबसे बड़े राष्ट्रव्यापी पशु देखभाल शिविरों के आयोजन के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड्स युनियन में शामिल किया गया। इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट ने 2025 में एक उल्लेखनीय विश्वस्तरीय उपलब्धि हासिल की, जब पशु विकास दिवस ने देश भर की कई लोकेशनों में एक साथ 'सबसे बड़े कैटल वैलफेयर लैसन' के लिए गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया- जिससे ग्रामीण कल्याण, पशुओं की देखभाल और बड़े पैमाने पर सामुदायिक विकास के लिए कंपनी की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता और मजबूत हुई।

महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने बिलासपुर यार्ड रिमॉडलिंग कार्यों का गहन निरीक्षण किया

बिलासपुर। श्री तरुण प्रकाश, महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने आज बिलासपुर यार्ड का विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण में बिलासपुर यार्ड में चल रहे यार्ड रिमॉडलिंग कार्यों की प्रगति की समीक्षा तथा कार्यों को समयबद्ध, सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने पर ज़ोर दिया गया । निरीक्षण के दौरान महाप्रबंधक ने आरआरआई और सिग्नलिंग गुमटी से संबन्धित कार्यों का गहन अवलोकन किया और संबंधित अधिकारियों से तकनीकी पहलुओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने ड्रॉइंग एवं लेआउट के माध्यम से यार्ड रिमॉडलिंग से संबंधित विभिन्न चरणों, ट्रैक व्यवस्था, सिग्नलिंग प्रणाली तथा भविष्य की परिचालन आवश्यकताओं की समीक्षा की। महाप्रबंधक ने अधिकारियों को दिशा-निर्देश देते हुए सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने तथा निर्माण के प्रत्येक चरण में सुरक्षा मानकों, संरक्षा नियमों और गुणवत्ता नियंत्रण पर विशेष ध्यान देने पर ज़ोर दिया । यार्ड रिमॉडलिंग पूर्ण होने के उपरांत रेल परिचालन अधिक सुगम, सुरक्षित एवं कुशल होगा, जिससे माल एवं यात्री ट्रेनों के संचालन में उल्लेखनीय सुधार आएगा। इस अवसर पर अपर महाप्रबंधक सहित संबन्धित विभागों के विभागाध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान कार्यों से संबन्धित विभागों के बीच समन्वय के साथ कार्य करने तथा किसी भी प्रकार की तकनीकी अथवा परिचालन चुनौती का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मरवाही में विधायक ने सोनोग्राफी जांच केंद्र का किया शुभारंभ.....

गौरेला पेंड्रा मरवाही। स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ एवं सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मरवाही में विधायक श्री प्रणव कुमार मरपच्ची ने शुक्रवार को सोनोग्राफी जांच केंद्र का फीता काटकर एवं पूजा-अर्चना के साथ विधिवत शुभारंभ किया। विधायक श्री मरपची शुभारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर उन्होंने खण्ड चिकित्सा अधिकारी डॉ. हर्षवर्धन मेहर को सोनोग्राफी लाइसेंस भी प्रदान किया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के मार्गदर्शन एवं कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी के प्रयासों से सोनोग्राफी केंद्र के प्रारंभ होने से क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं को अब स्थानीय स्तर पर ही जांच सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे उन्हें जिला मुख्यालय जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और समय व खर्च दोनों की बचत होगी। उद्घाटन अवसर पर चिकित्सा अधिकारी डॉ. अनुराधा विश्वास द्वारा 6 गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी जांच कर रिपोर्ट प्रदान की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रामेश्वर शर्मा ने कहा कि यह सोनोग्राफी सुविधा गर्भवती महिलाओं के समय पर परीक्षण में सहायक होगी तथा मातृ मृत्यु दर को कम करने में मील का पत्थर साबित होगा।कार्यक्रम में जिला कार्यक्रम प्रबंधक सुश्री विभा टोप्पो, जे.पी. सिंह, अरविंद कुमार, संतोष सोनी, नरेश्वर दास, सीपी गढ़ेवाल, अंबर जायसवाल सहित अनेक लोग उपस्थित रहे।

बाल विवाह मुक्त अभियान के तहत एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित

बिलासपुर। महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से लॉ स्टूडेंट्स, एमएसडब्ल्यू स्टूडेंट्स एवं युवोदय वॉलंटियर्स के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन जल संसाधन विभाग के प्रार्थना सभा भवन में किया गया। यह कार्यशाला विशेष रूप से लॉ स्टूडेंट्स, एमएसडब्ल्यू स्टूडेंट्स एवं युवोदय वॉलंटियर्स के लिए आयोजित की गई थी। जिले के विभिन्न विकासखंडों से प्रतिभागियों को आमंत्रित किया गया था और प्रशिक्षण का मुख्य फोकस इन्हीं पर केंद्रित रहा। कार्यक्रम बाल विवाह मुक्त अभियान के अंतर्गत आयोजित किया गया, जिसमें युवाओं की भूमिका को विशेष रूप से रेखांकित किया गया। प्रशिक्षण मुख्य रूप से लॉ स्टूडेंट्स, एमएसडब्ल्यू स्टूडेंट्स एवं युवोदय वॉलंटियर्स को प्रदान किया गया, ताकि वे अपने-अपने क्षेत्रों में बाल विवाह की रोकथाम, बाल संरक्षण मामलों की पहचान तथा आवश्यक कानूनी एवं प्रशासनिक प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से समझकर जागरूकता एवं सहयोग की भूमिका निभा सकें। इस अवसर पर श्री शशांक शर्मा एवं एनी रोज टोडर द्वारा प्रतिभागियों को विस्तारपूर्वक प्रशिक्षण दिया गया। सत्र में बाल विवाह से संबंधित कानूनी प्रावधान, फोस्टर केयर एवं स्पॉन्सरशिप की प्रक्रिया, जोखिमग्रस्त बच्चों की पहचान, समय पर रिपोर्टिंग एवं विभागीय समन्वय जैसे विषयों पर स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान किया गया।कार्यशाला में स्कूल के छात्र-छात्राओं की भी उपस्थिति रही, जिससे जागरूकता का सकारात्मक वातावरण बना। साथ ही डीसीपीयू विभाग के सभी संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे और उन्होंने भी अपने स्तर से मार्गदर्शन साझा किया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं एवं वॉलंटियर्स को सशक्त बनाना था, ताकि वे अपने क्षेत्र में बाल विवाह मुक्त समाज की दिशा में सक्रिय भूमिका निभा सकें तथा बाल संरक्षण तंत्र को मजबूत करने में सहयोगी बन सकें।

बेख़ौफ़ दौड़ रहे रेत से लदे भारी वाहन, प्रशासन की अनदेखी पर उठे सवाल

बिलासपुर। शहर की सड़कों पर इन दिनों रेत और बिल्डिंग मटेरियल से लदे भारी वाहनों की आवाजाही आम होती जा रही है। मुख्य मार्गों और व्यस्त चौक-चौराहों पर हाईवा और ट्रैक्टर बेख़ौफ़ दौड़ते नजर आ रहे हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका लगातार बनी हुई है। ताज़ा मामला बिलासपुर शहर के अशोकनगर चौक स्थित सीपत रोड, सरकंडा क्षेत्र का है। यहां नो-एंट्री के समय भी भारी वाहन बेधड़क सड़कों पर फर्राटा भरते देखे जा सकते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन वाहनों के मालिकों और चालकों को न तो प्रशासन का कोई भय है और न ही आम नागरिकों की सुरक्षा की चिंता। प्रतिदिन स्कूल जाने वाले बच्चे, दफ्तर आने-जाने वाले कर्मचारी और आम राहगीर इन भारी वाहनों के बीच से गुजरने को मजबूर हैं। सड़क सुरक्षा नियमों की खुलेआम अनदेखी हो रही है, जिससे किसी भी समय बड़ी दुर्घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि नो-एंट्री समय में सख्ती से भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई जाए और नियमित जांच अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन समय रहते कार्रवाई करता है या फिर किसी बड़े हादसे के बाद ही सख्ती दिखाई जाएगी।

नाम परिवर्तन की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरे पुत्री के शैक्षणिक दस्तावेजो में नाम नाम स्वेता वर्मा पिता बेनु सिंह वर्मा अंकित है, उसी प्रकार आधार कार्ड में नाम सुवेता वर्मा पिता बेनु सिंह वर्मा दर्ज है, किन्तु भूमि संबंधी दस्तावेज / अभिलेखो में नाम लिसिका पटेल पिता मूलचंद पटेल दर्ज है जो कि सभी नाम एक ही व्यक्ति का है, चूंकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम स्वेता वर्मा पिता बेनु सिंह वर्मा है जो कि सत्य एवं सही है तथा नाम मे एकरूपता लाने हेतु इसी नाम को समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेज में लिखा व पढा जाना व पहचाना एवं संबोधित किया जावे । ।

सूचना जाने ।

भवदीय
बेनु सिंह वर्मा पिता कल्याण सिंह वर्मा
निवाशी ग्राम रजकुडी पो बेमेतरा
तहसील व्जिला बेमेतरा

नाम परिवर्तन की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरे पुत्री के शैक्षणिक दस्तावेजो में नाम नाम गंगा दास वैष्णव पिता भुवन दास अंकित है, उसी प्रकार आधार कार्ड में नाम जगमोहन देवांगन पिता भुवन दास दर्ज है, किन्तु भूमि संबंधी दस्तावेज /अभिलेखो में नाम लिसिका पटेल पिता मूलचंद पटेल दर्ज है जो कि सभी नाम एक ही व्यक्ति का है, चूंकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम गंगा दास वैष्णव पिता भुवन दास है जो कि सत्य एवं सही है तथा नाम मे एकरूपता लाने हेतु इसी नाम को समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेज में लिखा व पढा जाना व पहचाना एवं संबोधित किया जावे ।।

सूचना जाने ।

भवदीय
गंगा दास वैष्णव पिता भुवन दास तहसील
साजा जिला बेमेतरा
निवासी ग्राम गतापर पो परपोडी

न्यायालय कार्यपालिक दण्डाधिकारी थानखम्हरिया जिला बेमेतरा (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र...../ब-121 सन 2025-26

पिता एतूद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक बिसराम साहू पिता दयाराम जाति तेली निवासी ग्राम किरकी तहसील थानखम्हरिया जिला बेमेतरा के द्वारा आवेदन पेश किया कि उनके पत्नी उर्मिला का मृत्यु दिनांक 26/03/2006 को ग्राम किरकी में हुआ है। अतएव जिस किसी को आपत्ति हो तो, दावा आपत्ति पेशी दिनांक 09/03/2026 तक कार्यालय में उपस्थिति होकर दावा आपत्ति पेश कर सकते हैं।

आवेदक अपने पत्नी नाम उर्मिला साहू का मृत्यु प्रमाण पत्र की मांग कि गई है, जो देने हेतु इस न्यायालय में आवेदन लंबित है।

अत: आज दिनांक 23/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय कि पद मुद्रा सहित जारी किया गया ।

कार्यपालिक दण्डाधिकारी
थानखम्हरिया
जिला- बेमेतरा

मुहर

न्यायालय तहसीलदार बेमेतरा, तहसील व जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

// ईश्तहार //

क्र./653/प्र.1/तह./2026
बेमेतरा, दिनांक.....
रा.प्र.क्र., ब-121 वर्ष 2025-26

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक योगेश वर्मा पिता जोहन वर्मा निवासी ग्राम भीमपुरी तहसील बेमेतरा जिला बेमेतरा के द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अपने दादा कार्तिक वर्मा पिता कुंवर के मृत्यु पंजीयन हेतु आवेदन पेश किया गया है। जिनकी मृत्यु दिनाँक 23.02.2020 को ग्राम भीमपुरी तहसील व जिला बेमेतरा में होना और भूलवश मृत्यु का पंजीयन नहीं करा पाना बताया गया है।

उक्त आवेदन पत्र के संबंध में जिस किसी को दावा / आपत्ति हो तो वे नियत पेशी तारीख 05/03/26 तक इस न्यायालय में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी दावा / आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

आज दिनाँक 16/02/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर सहित ईश्तहार जारी।

तहसीलदार
बेमेतरा

मुहर

न्यायालय नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी मुंगेली-2 (खैरा-सेतगंगा) जिला-मुंगेली (छ.ग.)

// ईश्तहार //

रा.प्र.क./.....
/ब-121/2025-26
ग्राम-केशली कला
प.ह.नं. 01
तहसील व जिला-मुंगेली

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक / आवेदिका वैधनाथ भास्कर पिता/पति तिरिथराम जाति सतनामी साकिन केशलीकला तहसील व जिला-मुंगेली (छ.ग.) द्वारा ग्राम केशलीकला प.ह.नं. 01 तहसील व जिला मुंगेली निवासी अपने पुत्री सोनिया पिता बैघनाथ का जन्म / मृत्यु दिनांक 16/05/2007 को होने के फलस्वरूप नगरपालिका / सचिव, ग्राम पंचायत केशलीकला में दर्ज कराने हेतु इस न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

तत्संबंध में यदि किसी को कोई दावा/आपत्ति पेश करना हो तो वह स्वयं, अभिभावक या प्रतिनिधि के माध्यम से दिनांक 11/03/2026 समय प्रात: 11:00 बजे दावा/आपत्ति इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि पश्चात् प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नही किया जायेगा।

ईश्तहार आज दिनांक 24/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की जारी किया गया।

कार्यपालिका दण्डाधिकारी
मुंगेली

मुहर

विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल जारी

12 टीमें खेलेंगी 33 मुकाबले, पाकिस्तान के खिलाफ मैच से शुरू होगा भारत का अभियान

इंग्लैंड। अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा हैं। मेजबान इंग्लैंड 12 जून को टूर्नामेंट के उद्घाटन मुकाबले में श्रीलंका से खेलेगा। टूर्नामेंट का 10वां एडिशन 12 जून से 5 जुलाई तक खेला जाएगा। टीम इंडिया 14 जून को अपना अभियान इस टूर्नामेंट में शुरू करेगी। भारतीय टीम का पहला मुकाबला पाकिस्तान के साथ होगा। टीम इंडिया के ग्रुप में पाकिस्तान के अलावा ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और नीदरलैंड भी मौजूद हैं।

दोनों ग्रुप से टॉप-2 टीमें सेमीफाइनल खेलेंगी

आईसीसी ने 12 टीमों को 6-6 टीमों के 2 ग्रुप में बांटा है। इन दोनों ग्रुप की टॉप पर रहने वाली दो-दो टीमें सेमीफाइनल में क्वॉलिफाई करेंगी।

आईसीसी के सीईओ का बयान

आईसीसी के सीईओ संजोग गुप्ता ने कहा, विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल जारी होना, इस ग्लोबल प्रीमियर स्पोर्टिंग इवेंट से पहले एक अहम पड़ाव है। यह इवेंट द्रष्टि के विमेंस क्रिकेट में लगातार इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है, जिसमें ज्?यादा भागीदारी और हाई-परफॉर्मेंस के तरीके, इवेंट और प्रोडक्शन स्टैंडर्ड, टूर्नामेंट प्राइज मनी, मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन और कमर्शियल पार्टनरशिप शामिल हैं।

ऑस्ट्रेलिया सबसे सफल टीम रही

विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया सबसे सफल टीम रही है। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक रिकॉर्ड छह बार खिताब अपने नाम किया है और कई बार फाइनल तक पहुंचकर अपनी बादशाहत साबित की है। इसके अलावा इंग्लैंड ने 2009 में पहला एडिशन जीतकर इतिहास रचा, जबकि वेस्टइंडीज ने 2016 में खिताब जीता था।

ICC विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप्स

ग्रुप 1

भारत	सा. अफ्रीका	ऑस्ट्रेलिया
पाकिस्तान	बांग्लादेश	नीदरलैंड्स

ग्रुप 2

वेस्टइंडीज	इंग्लैंड	न्यूजीलैंड
श्रीलंका	आयरलैंड	स्कॉटलैंड

ब्रीफ न्यूज

बीसीएल में खेलते नजर आयेंगे धवन

मुम्बई । हाल में आयरलैंड की सोफी शाइन से दूसरी शादी करने वाले पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन अब बिग क्रिकेट लीग (बीसीएल) के दूसरे सत्र में खेलते नजर आएंगे। धवन बीसएल के दूसरे सत्र में 'यूपी ब्रिज स्टार्स' की ओर से खेलेंगे। धवन जैसे अनुभवी क्रिकेटर का लाभ टीम के युवाओं को मिलेगा। इससे पहले इसे लीग के पहले सत्र में भी धवन ने अच्छा प्रदर्शन कर सभी को प्रभावित किया था। बिग क्रिकेट लीग का आयोजन ग्रेटर नोएडा के खेल परिसर में होगा। ये टूर्नामेंट 11 मार्च से शुरु होगा और इसका खिताबी मुकाबला 22 मार्च को खेला जाएगा।

यूपी ब्रिज स्टार्स प्रबंधन को उम्मीद है कि धवन की कप्तानी में टीम बेहतर प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज करेगी। उनके रहने से से युवा खिलाड़ियों को भी सीखने का काफी अवसर मिलेगा।बीसएल एक ऐसा टूर्नामेंट हैं जिसमें गली-मोहल्लों में खेलने वाले प्रतिभाशाली क्रिकेटरों को अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय सितारों के साथ खेलने का अवसर मिलता है। इस लीग में डॉक्टर, इंजीनियर, दुकानदार, वकील, किसान या किसी भी अन्य पेशे से जुड़ा व्यक्ति खेल सकता है। खास बात ये है कि आम खिलाड़ियों को भी अंतररष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ खेलने का अवसर मिलता है।

पैरी और गार्थ ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम से बाहर हुई, मेगन और हैमिल्टन शामिल

सिडनी । ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम भारत के खिलाफ एकदिवसीय सीरीज में ऑलराउंडर एलिसी पैरी और तेज गेंदबाज किम गार्थ के बिना ही उतरेगी। इसका कारण है कि ये दोनो ही फिट नहीं होने के कारण सीरीज से बाहर हो गयी हैं। ये दोनों खिलाड़ी सरे टी20 के दौरान घायल हो गयी थीं। एकदिवसीय ही नहीं 6 मार्च से पर्थ में शुरू होने वाले एकमात्र टेस्ट में भी ये शायद ही खेल पायें।

पेरी ने कहा कि टी20 सीरीज के दौरान उन्हें हल्की चोट लगी थी। जांच के बाद उन्हें आराम के लिए कहा गया है। पेरी और गार्थ के बाहर होने से अनुभवी तेज गेंदबाज मेगन शुट और युवा ऑलराउंडर लूसी हैमिल्टन को टीम में शामिल किया गया है। शुट ने वापसी करते ही टी20 में भारतीय ओपनर प्रतीका रावल का विकेट लिया। वहीं हैमिल्टन ने गवर्नर-जनरल इलेवन की ओर से खेलते हुए शेफाली वर्मा का विकेट लिया था। एकदिवसीय सीरीज में पेरी का प्रदर्शन औसत रहा है।

ऑस्ट्रेलिया की एकदिवसीय टीम

एलिसा हीली (कप्तान), फोएबे लिचफील्ड, जॉर्जिया वॉल, बेथ मूनी (विकेटकीपर), एनेबेल सदरलैंड, एशले गार्डनर, टाहलिया मैक्ग्रा, सोफी मोलिन्यू, अलाना किंग, मेगन शुट, डार्सी ब्राउन, जॉर्जिया वेयरहम, निकोला कैरी, लूसी हैमिल्टन।

इंग्लैंड टी-20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम

पाकिस्तान को 2 विकेट से हराया; हैरी ब्रूक का शतक, शाहीन के 4 विकेट बेकार

पल्लेकेले। इंग्लैंड टी-20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। टीम ने मंगलवार रात को पाकिस्तान पर 2 विकेट की जीत दर्ज की। श्वहत्र इस एडीशन के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी है। टूर्नामेंट के इतिहास में इंग्लिश टीम ने लगातार सबसे ज्यादा 5वीं बार सेमीफाइनल में प्रवेश किया है।

कैंडी के पल्लेकेले स्टेडियम में इंग्लैंड ने 165 रन का टारगेट 19.1 ओवर में 8 विकेट पर चेज कर लिया। जोफ्रा आर्चर ने सलमान मिर्जा की बॉल पर चौका मारकर जीत दिलाई।

कप्तान हैरी ब्रूक ने 51 गेंद पर 100 रन की पारी खेली। इसमें 10 चौके और 4 छक्के शामिल रहे। विल जैक्स ने नाबाद 28 रन बनाए। शाहीन शाह अफरीदी ने 4 विकेट झटके। उस्मान तारिक को दो विकेट मिले।

इससे पहले टॉस जीतकर बैटिंग कर रही पाकिस्तानी टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 164 रन बनाए। साहिबजादा फरहान ने 63 रनों की पारी खेली। जबकि बाबर आजम और फखर जमान ने 25-25 रन का योगदान दिया। इंग्लैंड की ओर से लियाम डॉसन ने 3 विकेट झटके। जोफ्रा आर्चर और जैमी ओवरटन को 2-2 विकेट मिले। आदिल रशीद को एक विकेट मिला। एक बैटर रनआउट हुए।

पाकिस्तान के लिए फरहान ने जड़ा पचासा

इससे पहले, पाकिस्तान की ओर से सिर्फ साहिबजादा फरहान ने अर्धशतक लगाया जिसकी मदद से टीम चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दे सकी। फरहान ने 45 गेंदों पर सात चौकों और दो छक्कों की मदद से 63 रन बनाए। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पावरप्ले में दो झटके दिए थे, लेकिन फरहान ने बाबर आजम के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 46 रन जोड़े। बाबर 24 गेंदों पर 25 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद फरहान और फखर जमां के बीच चौथे विकेट के लिए 49 रनों की साझेदारी हुई, लेकिन ओवरटन ने फरहान को अपना शिकार बनाया।

टी20 विश्व कप में शतक लगाने वाले पहले कप्तान

लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और शाहीन अफरीदी ने टीम को लगातार झटके दिए। शाहीन ने पहली ही गेंद पर फिल सॉल्ट को खाता खोले बिना पवेलियन भेजा और फिर जोस बटलर को आउट किया जो दो रन बनाकर आउट हुए। शाहीन ने फिर पावरप्ले के दौरान जैकब बेथेल को आउट कर इंग्लैंड को तीसरा झटका दिया। बेथेल आठ रन बनाकर पवेलियन लौटे। हालांकि, ब्रूक टिके रहे और उन्होंने जिम्मेदारी से खेलते हुए पारी आगे बढ़ाई। ब्रूक ने पहले 28 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया और फिर 50 गेंदों पर शतक लगाया। ब्रूक टी20 विश्व कप में शतक लगाने वाले पहले कप्तान हैं। इतना ही नहीं, ब्रूक टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में क्रिस गेल को पीछे छोड़ा जिन्होंने 2010 में भारत के खिलाफ 98 रन बनाए थे।

टी-20 वर्ल्डकप मैच में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड बना

टी20 वर्ल्ड कप के किसी मैच में सबसे ज्यादा छक्के

छक्के	मैच	जगह	साल
31	वेस्टइंडीज vs जिम्बॉब्वे	मुंबई	2026
30	आयरलैंड vs नीदरलैंड	सिलहट	2014
25	इंग्लैंड vs इटली	कोलकाता	2026
24	ऑस्ट्रेलिया vs भारत	ग्रॉस इसलेट	2024
24	ऑस्ट्रेलिया vs भारत	ब्रिजटाउन	2010

मुंबई। पॉवेल ने सिकंदर रजा का माथा चूमा, हेटमायर ने 108 मीटर का सिक्स लगाया टी-20 वर्ल्ड कप के चौथे सुपर-8 मैच में वेस्टइंडीज ने सोमवार को जिम्बाब्वे पर 107 रन की जीत दर्ज की। मुंबई के वनखड़े स्टेडियम में जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 254 रन बनाए। 255 रन का टारगेट चेज कर रही जिम्बाब्वे 17.4 ओवर में 147 रन पर ऑलआउट हो गई। 19 बॉल पर फिफ्टी लगाने वाले शिमरोन हेटमायर प्लेयर ऑफ द मैच रहे। इस मैच में 10 रिकॉर्ड और रोचक मोमेंट्स देखने को मिले। **टी-20 वर्ल्ड कप के एक मैच में सबसे ज्यादा सिक्स लगे**

इस मैच में कुल 31 छक्के लगे। यह टी-20 वर्ल्ड कप इतिहास में किसी एक मैच में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड है। पिछला रिकॉर्ड 30 सिक्स का था। जो 2014 में आयरलैंड और नीदरलैंड के मैच में बना था। यह मैच सिलहट में खेला गया था।

हेटमायर ने टी-20 वर्ल्ड कप में विंडीज के लिए सबसे तेज फिफ्टी लगाई

जिम्बाब्वे के खिलाफ शिमरोन हेटमायर ने 19 गेंद पर फिफ्टी लगाई। यह टी20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज की ओर से सबसे तेज फिफ्टी है। वे इसी एडीशन में स्कॉटलैंड के खिलाफ ईडन गार्डन्स में 22 गेंदों पर फिफ्टी बना चुके हैं। हेटमायर से पहले यह रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम था। गेल ने 2012 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोलंबो में 23 बॉल पर अर्धशतक लगाया था।

रहस्यमयी नॉर्थ कोरिया की फुटबॉल डिप्लोमेसी

16 साल बाद एशियन मंच पर वापसी कर रही महिला टीम, ऑस्ट्रेलिया में खेलेगी

सिडनी। दुनिया के सबसे रहस्यमयी देशों में शुमार नॉर्थ कोरिया एक बार फिर सुर्खियों में है। एक मार्च से ऑस्ट्रेलिया में शुरू हो रहे विमंस एशियन कप में नॉर्थ कोरिया की महिला फुटबॉल टीम हिस्सा लेने जा रही है। लंबे समय तक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से लगभग गायब रहने के 16 साल बाद वर्ल्ड नंबर-9 टीम टूर्नामेंट में उतर रही है।नॉर्थ कोरिया के महिला फुटबॉल की कहानी 1986 में शुरू हुई थी। कहा जाता है कि जब फीफा कांग्रेस में महिलाओं के लिए वर्ल्ड कप की मांग उठी, तो नॉर्थ कोरियाई प्रतिनिधियों ने इसे अपनी गिरती राजनीतिक साख को बचाने के एक मौके के तौर पर देखा। नॉर्थ कोरिया ने एक सोची-समझी रणनीति के तहत महिलाओं के खेल में भारी निवेश किया।

सफल खिलाड़ी 'नेशनल हीरो' थीं, इनाम में घर दिए जाते थे

नॉर्थ कोरिया ने 2001 से 2008 के बीच तीन एशियन कप खिताब जीते। प्योंगयोंग के 1.5 लाख की क्षमता वाले स्टेडियम में महिला फुटबॉल मैच देखने भीड़ उमड़ती थी। सफल खिलाड़ियों को 'नेशनल हीरो' माना जाता। खिलाड़ियों को सफलता के बदले अपार्टमेंट और राजधानी में रहने का अवसर मिलता था, जहां जीवन स्तर ग्रामीण इलाकों से बेहतर माना जाता है। सरकार ने डाक टिकट, पोस्टर और टीवी धारावाहिकों के जरिए महिला फुटबॉल को राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक के रूप में पेश किया था।

ऑस्ट्रेलिया की जीत से शुरुआत, पहले वनडे में चोटिल हुई हरमनप्रीत

ब्रसबेन। ारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिसबेन में पहला वनडे मैच खेला गया। इस दौरान भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर चोटिल हो गई और फील्डिंग के लिए नहीं उतरीं। बीसीसीआई ने हरमनप्रीत की फिटनेस को लेकर जानकारी दी है।

भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच के दौरान चोटिल हो गईं। हरमनप्रीत इसके चलते फील्डिंग के लिए भी नहीं उतरीं। उन्हें बल्लेबाजी करते वक्त घुटने में चोट लगी थी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने हरमनप्रीत की फिटनेस को लेकर अपडेट दिया है और बताया है कि बोर्ड की मेडिकल टीम हरमनप्रीत की फिटनेस पर निगरानी रख रही है।

बीसीसीआई ने हरमनप्रीत की फिटनेस पर अपडेट देते हुए कहा, कप्तान हरमनप्रीत कौर बल्लेबाजी के दौरान बाएं घुटने में चोट लगने के कारण दूसरी पारी में मैदान पर नहीं उतरीं। बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी स्थिति पर नजर रख रही है। उनकी अनुपस्थिति में उपकप्तान स्मृति मंधाना ने टीम की कप्तानी की।

मंधाना-हरमनप्रीत का अर्धशतक गया बेकार

ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिसबेन के एलन बॉर्डर फील्ड में खेले तीन वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में भारत को छह विकेट से हरा दिया। कप्तान हरमनप्रीत कौर और उपकप्तान स्मृति मंधाना के अर्धशतक पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली और बेथ मूनी की पारी भारी पड़ी। सीरीज का दूसरा मुकाबला 27 फरवरी को होबार्ट में खेला जाएगा। भारत की शुरुआत खराब रही जिसके बाद मंधाना ने कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ चौथे विकेट के लिए 72 गेंदों में 48 रन जोड़कर भारत का शतक पूरा करवाया। मंधाना 68 गेंदों में 7 चौकों के साथ 58 रन बनाकर आउट हुईं, जिसके बाद कप्तान कौर ने पारी को संभाला। हरमनप्रीत कौर ने 84 गेंदों में 53 रन की पारी खेली, जिसमें 3 चौके शामिल रहे।

ऑस्ट्रेलिया की जीत से शुरुआत

भारत ने तीन मैचों की टी20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराया था, लेकिन वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने जीत से शुरुआत की है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए हरमनप्रीत और स्मृति मंधाना के अर्धशतकों से 48.3 ओवर में 214 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने एलिसा हीली और बेथ मूनी के अर्धशतकों तथा एनाबेल सदरलैंड की शानदार बल्लेबाजी से 38.2 ओवर में चार विकेट पर 217 रन बनाकर जीत दर्ज की। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है।

लीवरपूल में इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में मैनचेस्टर यूनाइटेड और एवरटोन के बीच मैच में खेलते हुए खिलाड़ी।

यावर हसन और शुभम पुंदीर की फिफ्टी; प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए

रणजी ट्रॉफी फाइनल- टी-ब्रेक तक जम्मू-कश्मीर का स्कोर 178/2

मुंबई। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का फाइनल कर्नाटक और जम्मू-कश्मीर के बीच हुबली क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है। जम्मू-कश्मीर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है। पहले दिन टी-ब्रेक तक जम्मू-कश्मीर ने 2 विकेट खोकर 178 रन बना लिए हैं। शुभम पुदीर 64 रन और पारस डोगरा 9 रन बनाकर खेल रहे हैं। वहीं ओपनर यावर हसन ने 88 रनों की पारी खेली, जबकि कमरान इकबाल सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हुए। दोनों ही विकेट प्रसिद्ध कृष्णा ने लिए हैं।

शुभम पुदीर की फिफ्टी

जम्मू कश्मीर की ओर से नंबर-3 पर बल्लेबाजी कर रहे शुभम पुदीर फिफ्टी पूरी कर चुके हैं। उनके अलावा, यावर हसन ने भी अर्धशतक लगाया। जम्मू-कश्मीर ने 18 रन पर गंवाया पहला विकेट टॉस जीतकर बैटिंग कर रही जम्मू-कश्मीर की शुरुआत खराब रही। टीम ने 18 रन के स्कोर पर पहला विकेट गंवा दिया था। यहां पर करीम इकबाल 6 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें प्रसिद्ध कृष्णा ने विकेटकीपर केएल राहुल के हाथों कैच कराया।

जम्मू-कश्मीर की पहली पारी

जम्मू कश्मीर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। कामरान इकबाल छह रन बनाकर जल्दी आउट हो गए। इसके बाद यावेर हसन और शुभम पुंडीर ने दूसरे विकेट के लिए 139 रन की साझेदारी निभाई। यावेर शतक से चूक गए। वह 150 गेंद पर 13 चौके की मदद से 88 रन बनाकर आउट हुए। शुरुआती दोनों विकेट प्रसिद्ध कृष्णा को मिले। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए उतरे कप्तान पारस डोगरा नौ रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो गए। तब से शुभम और समद ने पारी संभाली।

शुभम और यावर के बीच शतकीय साझेदारी

पहला विकेट जल्दी गिरने के बाद शुभम पुंदीर बल्लेबाजी के लिए उतरे। शुभम और यावर हसन ने दूसरे विकेट के लिए 139 रनों की साझेदारी की। दोनों ने करीब 40 ओवर तक बैटिंग की। इस बीच यावर और शुभम ने अपने अर्धशतक भी पूरे किए।

प्रसिद्ध ने तोड़ी शतकीय साझेदारी

शुभम पुंदीर और यावर हसन की शतकीय साझेदारी को प्रसिद्ध कृष्णा ने ब्रेक किया। उन्होंने 51वें ओवर की छठी बॉल पर यावर हसन को विकेटकीपर केएल राहुल के हाथों कैच कराया। यावर ने150 बॉल पर 88 रन बनाए।

जम्मू-कश्मीर ने दो बदलाव किए

फाइनल में जम्मू-कश्मीर ने दो बदलाव किए हैं। बैटर शुभम खजुरिया की जगह कमरान इकबाल खेल रहे हैं, जबकि गेंदबाज वंशराज की जगह साहिल लोत्रा को जगह मिली है। दूसरी ओर कर्नाटक टीम में कोई बदलाव नहीं किया है। टीम सेमीफाइनल में खेली सेम टीम-कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरी है।

सारंगढ़ः रीवांपार पंचायत में 15वें वित्त की राशि का 'बंदरबांट',फर्जी बिलों के सहारे लाखों का गबन!

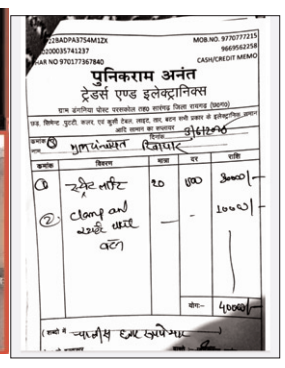

सारंगढ़/मूक पत्रिका

छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी 15वें वित्त योजना, जो ग्राम पंचायतों की तस्वीर बदलने के लिए बनाई गई थी, अब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। ताजा मामला सारंगढ़ जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत रीवापार का है, जहाँ सरपंच और सचिव ने मिलकर सरकारी खजाने में ऐसी सेंध लगाई है कि विकास कार्य सिर्फकागजों तक सिमट कर रह गए हैं।

GST के नियमों की धज्जियाँ, शासन को लगाया चूना —नियमों के मुताबिक, 15वें वित्त की राशि (टाईट और अनटाईट फंड) को स्वच्छता, नाली, बोर और जल संरक्षण जैसे कार्यों पर व्यय करना होता है। इसके लिए भुगतान केवल उन्हीं फर्मों को किया जा सकता है जिनके पास जीवित त्सस्ञ रजिस्ट्रेशन और वैध टिन नंबर हो। लेकिन रीवापार पंचायत में कायदे-कानूनों को ताक पर रखकर 'फर्जी बिलों' का खेल खेला गया। सिर्फ पैसा गबन करने के मंशा से त्सस्ञ बिल के सहारे लाखों रुपए आहरण कर लिए गए, जिसके पास कोई फर्म एवं किसी भी प्रकार की सामग्री मुलक दुकान नहीं है जिससे न केवल सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है बल्कि शासन को गुमराह भी किया गया है सिर्फ त्सस्ञ बिल छपवा कर कागजो में फर्म बताया गया है जबकि जमीनी स्तर पर फर्म संचालित ठप है!ट्रेडर्स पैसा कमाने के मंसा से त्सस्ञ बिल बनवा कर पंचायतों कों सिर्फ बिल उपलब्ध करा रहा है जिससे की वित्त की राशि निकाला जा सके। ट्रेडर्स के पास किसी भी प्रकार की कोई फर्म या सामग्री मूलक दूकान नहीं है यह सिर्फ त्सस्ञ बिल देकर पंचायत 2से 3परसेंट चार्ज करता है, ट्रेडर्स बिल उपलब्ध करवा कर पंचायतों में सिर्फ फर्जीवाड़ा कों बढ़ावा दें रहा है। वहीं ग्राम पंचायत कों आसानी से सामान खरीदे बीना ही बिल मील जा रहा,जिससे की ग्राम पंचायतों की विकास कार्य प्रभावित हो रहा है।

कागजों पर 'विकास', हकीकत में 'जेब गरम'–ग्रामीणों के बीच यह चर्चा आम है कि यदि सामग्री असली दुकान से खरीदी जाती, तो पक्का त्सस्ञ बिल जरूर मिलता। बिना बैध बिल लगाकर के राशि निकालना इस बात का पुख्ता सबूत है किः सामग्री की खरीदी ही नहीं हुई सिर्फ कागजों पर फर्जी बिल लगाकर पैसे निकाल लिए गए। विकास शून्य : जमीन पर कोई काम नहीं हुआ, जिससे ग्रामीणों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। भ्रष्ट गठजोड़ : सरपंच और सचिव ने आपसी मिलीभगत से शासन को गुमराह कर अपनी जेबें भरी हैं। अधिकारियों की 'मौन' सहमति या संरक्षण? हैरानी की बात यह है कि सारंगढ़ जनपद की कई पंचायतों में भ्रष्टाचार की खबरें लगातार प्रकाशित हो रही हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं। सवाल यह उठता है कि क्या इन भ्रष्टाचारियों को जनपद के उच्च अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है? बार-बार शिकायतों के बावजूद कार्यवाही न होना प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गहरा संदेह पैदा करता है। उक्त विषय पर सरपंच पति ने बताया की बिल व्हाउचर लगा है जो ग्राम डंगनिया का ही है।

कलेक्टर डॉ कंन्नौजे ने किसान सुभाष साहू के पाम ऑयल की खेती का किया निरीक्षण

कलेक्टर ने किसानों को पाम ऑयल की खेती के लिए प्रेरित करने अधिकारियों को दिए निर्देश

सारंगढ़ बिलाईगढ़,/मूक पत्रिका

कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे ने बरमकेला ब्लॉक के ग्राम पंचायत जामपाली में ऑयल पाम की खेती का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने किसानों से चर्चा कर पाम ऑयल की खेती को आय बढ़ाने वाला बेहतर विकल्प बताया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर डॉ. कन्नौजे ने उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि क्षेत्र के बड़े किसानों को पाम ऑयल की खेती के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि वैज्ञानिक पद्धति से इस फसल को अपनाया जाए तो किसानों को धान की अपेक्षा अधिक लाभ मिल सकता है।

कलेक्टर ने किसानों को शासन की योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि पाम ऑयल की खेती के लिए विभागीय स्तर पर तकनीकी मार्गदर्शन एवं आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने किसानों से आधुनिक खेती पद्धतियों को अपनाकर अपनी आय दोगुनी करने की दिशा में प्रयास करने का आह्वान किया। ग्राम जामपाली के किसान सुभाष साहू अपने 5 एकड़ खेत में पाम ऑयल की खेती कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस फसल से उन्हें पारंपरिक धान की खेती की तुलना में बेहतर लाभ मिलने की उम्मीद है।

पिछले वर्ष उन्होंने अपने खेत में धान की फसल ली थी और अब पाम ऑयल के साथ इंटरक्रॉपिंग के रूप में बैंगन लगाने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके।

घोषणाओं का पुलिंदा, जमीन पर कुछ नहींः सुनील सिंह का बजट पर हमला

बलरामपुर/मूक पत्रिका

जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुनील सिंह ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पेश किए गए 1,72,000 करोड़ रुपये के बजट पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे ÷घोषणाओं का बजट÷ करार दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत बजट में विकास और नवनिर्माण का स्पष्ट संकल्प नजर नहीं आता।

सुनील सिंह ने कहा कि सरकार ने पहले ÷ज्ञान÷ और ÷गति÷ थीम पर आधारित बजट पेश किए थे, जिनमें बड़े-बड़े वादे और घोषणाएं की गई थीं, लेकिन उनका लाभ धरातल पर कहीं दिखाई नहीं दिया। अब ÷संकल्प÷ थीम के नाम पर फिर लंबी-चौड़ी घोषणाएं की गई हैं, परंतु आम जनता को वास्तविक लाभ मिलेगा, ऐसा प्रतीत नहीं होता।

उन्होंने आरोप लगाया कि बस्तर और सरगुजा संभाग के विकास के नाम पर दिवास्वप्न दिखाया जा रहा है, जबकि बीते दो वर्षों में प्रदेश में ठोस उपलब्धियां नजर नहीं आई हैं। गांव, गरीब, किसान, मजदूर और युवाओं के लिए बजट में कोई ठोस प्रावधान नहीं है।

सुनील सिंह ने कहा कि कृषि प्रधान राज्य होने के बावजूद किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए बजट में कोई विशेष पहल दिखाई नहीं देती। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों के कारण किसान परेशान हैं और बजट में उन्हें राहत देने के लिए ठोस कदमों का अभाव है।उन्होंने यह भी कहा कि बलरामपुर जिले के लिए बजट में कोई विशेष घोषणा नहीं की गई है और स्थानीय जनता के हितों की अनदेखी की गई है।अंत में उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर यह बजट केवल शिगूफा और घोषणाबाजी तक सीमित नजर आता है, जिसमें जमीनी स्तर पर बदलाव की स्पष्ट दिशा दिखाई नहीं देती।

खनिज और शराब के अवैध गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश

कलेक्टर डॉ कन्नौजे ने ली कानून व्यवस्था और सड़क सुरक्षा की समीक्षा बैठक

होली पर्व के मद्देनजर शांति व्यवस्था , यातायात, प्रकृति और नागरिकों के जानमाल की सुरक्षा के मद्देनजर वन, राजस्व व पुलिस अधिकारियों को निर्देश

सारंगढ़ के भारत माता चौक के पास होने वाले गतिविधियों पर एसडीएम को प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने के निर्देश

सारंगढ़ में धरना- प्रदर्शन, पुतला दहन के लिए एसडीएम को वैकल्पिक स्थान चिन्हांकित करने के निर्देश

सारंगढ़ बस स्टैंड के पास नो-पार्किंग क्षेत्र में खड़ी टैक्सी और वाहनों पर चालानी कार्रवाई करने के निर्देश

सारंगढ़ बिलाईगढ़,/मूक पत्रिका

कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक ली। बैठक में पुलिस, वन, राजस्व, खनिज, नेशनल हाइवे, पीडब्लूडी, पशुधन और नगरपालिका आदि के अधिकारीगण उपस्थित थे। बैठक में होली पर्व के मद्देनज़र सुरक्षा इंतजाम, अवैध भंडारण और परिवहन के साथ साथ गौण खनिजो के अवैध खनन, अवैध शराब बिक्री, यातायात व्यवस्था, सड़क सुरक्षा को लेकर समीक्षा करते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए और कहा कि जिले में कानून व्यवस्था, यातायात व्यवस्था एवं अवैध गतिविधियों पर सख्ती से नियंत्रण रखा जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं हो। उन्होंने रेत, गिट्टी, पत्थर के

अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर सख्त नाराज़गी जताते हुए एसडीएम को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कलेक्टर डॉ कंन्नौजे ने कहा कि हाइवा और पोकलेन मशीनों के माध्यम से यदि कहीं भी अवैध खनन होता पाया जाता है तो संबंधितों पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए। विशेष रूप से रात्रिकालीन अवैध उत्खनन को लेकर खनिज विभाग को कड़ी निगरानी रखते हुए सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। अवैध शराब के विरुद्ध भी व्यापक अभियान चलाने के निर्देश देते हुए कलेक्टर ने कहा कि किसी भी हालत में अवैध शराब का विक्रय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।कानून व्यवस्था के मद्देनज़र भारत माता चौक के पास प्रतिबंधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। वहां किसी भी प्रकार का धरना- प्रदर्शन या पुतला दहन नहीं किया जाएगा। इसके लिए एसडीएम को पुतला दहन हेतु वैकल्पिक स्थान निर्धारित करने के निर्देश दिए गए। होली पर्व को देखते हुए जिले में फ्लैग मार्च आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि आमजन में सुरक्षा का भरोसा बना रहे। होली पर्व पर शांति व्यवस्था , यातायात, प्रकृति और नागरिकों के जानमाल की सुरक्षा के मद्देनजर वन, राजस्व व पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए। कलेक्टर द्वारा सारंगढ़ बस स्टैंड, मेन रोड, यात्री प्रतीक्षालयों के पास नो-पार्किंग क्षेत्र में खड़ी टैक्सी एवं अन्य वाहनों पर चालानी कार्रवाई करने के निर्देश राजस्व, पुलिस एवं नगरपालिका की टीम को दिए गए।

कलेक्टर ने सेजेस के नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया

जगदलपुर/मूक पत्रिका

कलेक्टर श्रीमती नूपुर राशि पन्ना ने बीते बुधवार को जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जिले के विभिन्न सेजेस विद्यालयों में संविदा भर्ती के नवनियुक्त 37 व्याख्याता, शिक्षकों एवं ग्रंथपाल को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस दौरान उन्होंने सभी नवनियुक्त शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी शीघ्र कार्यभार ग्रहण कर शिक्षकीय दायित्वों का बेहतर ढंग से निर्वहन करें। साथ ही विद्यालय में संयमित आचरण के साथ अनुशासित रहने को कहा। उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ विद्यालय और विद्यार्थियों के लिए नवाचार भी करने को प्रोत्साहित किया। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ अविनाश भोई, डिप्टी कलेक्टर सुश्री रश्मि पोया, जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती भारती प्रधान, वेणु गोपाल राव सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि जिले के सेजेस विद्यालयों के विभिन्न 42 रिक्त पदों पर संविदा भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित की गई थी, जिसके विरुद्ध 37 पदों की पूर्ति की गई है।

एनटीपीसी लारा के खिलाफधरना प्रदर्शन में सैकड़ो की संख्या में पीड़ित शामिल

सैकड़ों पीड़ित शामिल हुए एनटीपीसी-लारा के खिलाफधरना मे, पीड़ितों ने पूछा जिला प्रशासन से की एनटीपीसी के विरूद्ध कार्यवाही क्यों नहीं हो रही..?

कोयला, पानी और जमीन हमारे फिर भी एनटीपीसी के सामने बौने हुए छत्तसगढ़ीज ज्ञापन सौंपकर 10 दिन समयावधि दी गई

रायगढ़/मूक पत्रिका

एनटीपीसी-लारा परियोजना से प्रभावित भू-विस्थापितों एवं प्रभावित परिवारों की विभिन्न मांगों को लेकर आज लारा संघर्ष के नेतृत्व में एनटीपीसी-लारा के मुख्य द्वार के सामने निर्धारित धरना प्रदर्शन हुआ।लारा संघर्ष के आह्वान पर हुए इस धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि के बदले भू-विस्थापितों को न्याय दिलाना,समय रहते दर्जनों से ज्यादा लंबित समस्याओं का समाधान नहीं करना तथा जिला प्रशासन एवं एनटीपीसी परियोजना प्रबंधन की अनदेखी से हजारों पीड़ित परिवारों को हो रहे भीषण नुकसान के कारण प्रभावित परिवारों की स्थिति आर्थिक, सामाजिक और भौतिक रूप से बीते 15 वर्षों में कमजोर हो गई जिससे अब पीड़ितों के परिजनों हर तरफ से असहनीय स्थिति में आ गय है के लिए अब आंदोलन ही एक रास्ता बचा था जिसके लिए फिर से इसकी शुरुआत एक दिवसीय धरना से प्रारंभ हुई। एनटीपीसी लारा के विरूद्ध धरना प्रदर्शन में वक्ताओं ने बताया कि लगभग 15 वर्ष पूर्व जिला प्रशासन द्वारा छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय किसानों की भूमि अधिग्रहित कर एनटीपीसी-लारा परियोजना को सौंपी गई थी, परंतु आज तक भू-विस्थापित परिवारों को न तो नियमित रोजगार उपलब्ध कराया गया।

रेत के अवैध परिवहन पर राजस्व और पुलिस टीम ने की 12 ट्रेक्टरों पर कार्रवाई

सारंगढ़ बिलाईगढ़,/मूक पत्रिका

सारंगढ़ बिलाईगढ़, 25 फ़रवरी 2026/कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ संजय कन्नौजे के निर्देश पर रेत के अवैध परिवहन में संलिप्त 12 ट्रैक्टर पर सरिया के तहसीलदार कोमल साहू और थाना की टीम ने कार्यवाही करते हुए रेत से भरे वाहनों को सरिया थाना के सुरक्षार्थ में रखा है। यह कार्रवाई राजस्व और सरिया पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा किया गया है। राज्य के मुख्य सचिव ने सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में रेत के अवैध परिवहन को लेकर मीटिंग में नाराजगी जाहिर करते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद कलेक्टर संजय कन्नौजे ने जिले के सभी तहसील में राजस्व और पुलिस टीम में टास्क फोर्स का गठन कर कार्रवाई करने कहा गया था। उसी के परिपालन में मंगलवार और बुधवार को सरिया तहसीलदार कोमल साहू और थाना सरिया की टीम द्वारा सरिया क्षेत्र में रेत के अवैध परिवहन में संलिप्त 12 ट्रैक्टर पर कार्यवाही करते हुए थाना सरिया के सुरक्षार्थ में दिया गया। इनमें ट्रेक्टर के वाहन क्रमांक छ्त्त13रु2643, छ्त्त13श्व7957, 1 नया सोनालिका ट्रेक्टर आदि शामिल है। यह कार्यवाही छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 और खान एवं खनिज विकास अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत की गई। सरिया तहसीलदार कोमल साहू ने कहा कि इस तरह खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर संलिप्त सभी वाहनों पर लगातार कार्यवाही जारी रहेगा।

रबी एवं खरीफफसलों की खरीदी हेतु पंजीयन की अंतिम तिथि 28 फरवरी

सारंगढ़ बिलाईगढ़,/मूक पत्रिका

जिले में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान योजना (पीएम आशा) योजना अंतर्गत प्राईस सपोर्ट स्कीम के तहत किसानों का पंजीयन समितियों के माध्यम से ई समयुक्ति पोर्टल में किया जा रहा है। योजनान्तर्गत खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में क्रमशः अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफल्ली, सोयाबीन तथा रबी विपणन वर्ष 2026-27 में क्रमशः चना, मसूर एवं सरसों फसलों की बुआई करने वाले कृषक अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के माध्यम से सेवा सहकारी समितियों में आवेदन पत्र के साथ

आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर साथ लेकर अपना पंजीयन कराएं।इस योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसमें खरीफ फसल अरहर 8000 रूपए, मूंग 8768 रूपए, उड़द 7800 रूपए. मूंगफली 7263 रूपए. सोयाबीन 5328 रूपए एवं रबी फसल चना 5875 रूपए, मसूर 7000 रूपए, एवं सरसों 6500 रूपए, न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल तय किया गया है। योजनान्तर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जिले के लिए चिन्हांकित एजेंसी द्वारा पंजीकृत कृषकों की फसलों का खरीदी किया जाएगा।कृषकों से फसल उपार्जन का कार्य सप्ताह में 5 दिवस (सोमवार से शुक्रवार) तक किया जाएगा। योजनान्तर्गत शासन द्वारा पंजीकृत कृषकों से खरीफ फसल अरहर 3 क्विंटल, मूंग 3 क्विंटल, उड़द 3 क्विंटल, मूंगफली 7 क्विंटल, सोयाबीन 5 क्विंटल प्रति एकड़, एवं रबी फसल चना 6 क्विंटल, मसूर 2 क्विंटल, सरसों 5 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से कृषकों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी। कृषक अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के माध्यम से संबंधित सेवा सहकारी समिति में आवेदन पत्र के साथ ऋष्टा पुस्तिका, बी-1, पी-2, आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति जमा कर पंजीयन करा सकते हैं। योजना अंतर्गत शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जिले के लिए चिन्हांकित केंद्रीय एजेंसी द्वारा पंजीकृत कृषकों की फसलों का उपार्जन किया जाएगा। उप संचालक कृषि आशुतोष श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि प्राइस सपोर्ट स्कीम (पीएसएस) में किसानों का पंजीयन एकीकृत किसान पोर्टल एवं नाफेड द्वारा संचालित ई-समृद्धि पोर्टल के माध्यम से दलहन एवं तिलहन फसलों की ऑनलाईन पंजीयन कर खरीदी की जा रही है। इससे किसानों को समर्थन मूल्य की राशि सीधे उनके बैंक खातों में प्राप्त होगी। यह योजना दलहन-तिलहन क्षेत्र के विस्तार और किसानों की आय वृद्धि में महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) भारत सरकार की एक व्यापक योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना है। 2018 में शुरू की गई इस योजना में दालों, तिलहनों की खरीद शामिल है। इसमें तीन मुख्य घटक, मूल्य समर्थन योजना, मूल्य अंतर भुगतान योजना और निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना है । पीएम-आशा योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करना और आय में वृद्धि करना है। इसे वर्ष 2025-26 तक के लिए विस्तारित और मजबूत किया गया है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक आशिष कुमार कंठले द्वारा कलयुग का भारत द्वारा अग्रदूत कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, भाजपा कार्यालय के पास, रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)-492001 से मुद्रित एवं वार्ड नंबर 18 बाजार पारा बेमेतरा पोस्ट व जिला बेमेतरा छ.ग. पिन कोड 491335 से प्रकाशित । संपादक आशिष कुमार कंठले समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार मो. नं. 7999238079, 7828658259, समस्त विवादों का निपटारा बेमेतरा न्यायालय होगा।